सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 271, नई दिल्ली । मंगलवार, 10 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में कहां से किसको मिला और कटा टिक्ट
06 सीबीएसई/आईसीएसई/स्टेट बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक: तनाव को कैसे दूर रखें?
08 झारखंड विधानसभा का शपथ ग्रहण: किसी ने प्रणाम कर तो किसी ने नंगे पांव

दिल्ली परिवहन आयुक्त का नया आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली। हमने कल ही आपको जानकारी दी थी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में 13 निजी नंबर से पंजीकरण एवम् दिल्ली की जनता के वाहन संबंधी अन्य कार्यों, (ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, ड्राइवर एवम् कंडक्टर बेज, वाहन फ्यूल मोड में परिवर्तन, अल्टरेशन, चेसिस नंबर, इंटरनेशनल लाइसेंस, क्षेत्रीय वाहन डीलर लाइसेंस एवम् उनका नवीनीकरण, वाहन स्वामी के नाम, पते में परिवर्तन इत्यादि) को करने के लिए जनहित में उपलब्ध एवम् कार्यरत है। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था की परिवहन आयुक्त के निजी आदेश पर बिना जनता को पूर्व सूचना जारी किए ओर बिना इन्हें बंद करने के लिए अनिवार्य राजपत्र अधिसूचना जारी किए 9 क्षेत्रिय शाखाओं का विलय मात्र 4 शाखाओं में जो आज की तारीख़ में जमीनी स्तर पर कार्यरत रखी हुई है में कर दिया।

अब अपनी हठ का प्रयोग करते हुए परिवहन आयुक्त द्वारा 26 नवंबर की बैठक में जिसके मिनिट्स ऑफ मीटिंग 6 दिसंबर को जारी हुए हैं में 13 क्षेत्रीय शाखाओं को प्राप्त कोड को बंद करने के आदेश जारी कर एनआईसी को मात्र जमीनी स्तर पर चालित 4 क्षेत्रीय शाखाओं के कोड जारी करने के आदेश दिए हैं।

आपकी जानकारी हेतु बता दें इन चार क्षेत्रीय शाखाओं में से मात्र एक शाखा पर ही तकनीकी अधिकारी जिसके पास मोटर वाहन नियम के अनुसार अर्ध-न्यायिक शक्ति (Quasi Judicial Power) है जो इस प्रकार के पद पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के लिए अति आवश्यक है। अन्य तीन शाखाओं पर परिवहन आयुक्त द्वारा अपनी इच्छा के अधिकारी को जिनके पास यह शक्ति उपलब्ध नहीं है को नियुक्त कर रखा है।

अब आप स्वयं जाने जनहित का नाम लेकर आई दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार, जनहित के लिए नियुक्त मुख्य सचिव और सर्वोपरी प्रशासनिक उपराज्यपाल दिल्ली इस तरह हठ में जनता के लिए अहित करने और वह भी सिर्फ राजस्व में इजाफा करवाने और परिवहन विभाग के खर्चे में कटौती का नाम लेकर करने वाले एडिशनल मुख्य सचिव एवम् सीनियर आईएएस अधिकारी से इस बाबत स्पष्टीकरण तक मांगने को तैयार नहीं।

दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में चालित वाहनो की ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा जांच किस शाखा में शुरू हुई थी और वहां कितनी एटीएस की मशीनें आज भी धूल चाट रही हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग सदैव सभी प्रकार की नई तकनीक का प्रयोग करने में भारत देश में नंबर एक पर रहा है यह बात आप सभी जानते और मानते होंगे।

1. पहला राज्य जहां व्यवसायिक गतिविधि में डीजल चालित वाहनों पर पूर्ण पाबंदी लगा कर सीएनजी चालित वाहनों को लाया गया

2. पहला राज्य जहां महिला सुरक्षा का नाम लेकर वाहनों में जीपीएस जीपीआरएस वीएलटीडी संयंत्र लगवाया गया

3. पहला राज्य जहां फेस फ्री ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई

4. पहला राज्य जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आनलाइन टेस्ट प्रक्रिया शुरू की गई

5. पहला राज्य जहां लर्निंग लाइसेंस आनलाइन शुरू किया गया

6. पहला राज्य जहां व्यवसायिक गतिविधि में चालित वाहनो की जांच ऑटोमैटिक ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा शुरू की गई

जैसे अनगिनत कार्य हैं जिन्हें सर्वप्रथम करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली परिवहन विभाग के नाम पर है

आज आपको याद करवाते है अगर आप भूल गए हो तो दिल्ली से बुराड़ी वाहन जांच शाखा ही ऐसी शाखा है जहां वाहनों की जांच ऑटोमैटिक ट्रैकिंग सिस्टम पर शुरू की गई थी और आज भी वह सभी मशीनें उसी स्थान पर उपलब्ध है।

फिर ऐसा क्या है जो दिल्ली परिवहन आयुक्त उन्हें शुरू करवाने कि जगह वहां से वाहनों की जांच को सदैव जनता को परेशानी के साथ उनकी जान को जोखिम में डाल कर झूलझूली वाहन जांच शाखा में भेजने को तत्पर रहता हैं।

परिवहन आयुक्त भली भांति परिचित है की झूलझूली वाहन जांच शाखा में इतना वाहन जिनको प्रतिदिन जांच की आवश्यकता है हो ही नहीं सकता क्योंकि

1. उस जांच शाखा की उतनी क्षमता ही नहीं है,

2. उस क्षेत्र में वाहनों और वाहन मालिकों/ चालकों की सुरक्षा भी नहीं है

3. उस वाहन जांच शाखा में उपलब्ध ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम की कम्पनी का कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट भी समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका हैं ओर सिर्फ परिवहन आयुक्त की कृपा दृष्टि से उसे बार बार एक्टेंशन मिल रहा है

इसका अर्थ साफ है की दिल्ली की जनता की असुरक्षा की कीमत पर उस कम्पनी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्यों, बड़ा सवाल?

क्या परिवहन आयुक्त की अपनी इच्छा या ऊपर से किसी का दबाव???

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे देश का सबसे आधुनिक और हाई-टेक सड़क मार्ग कहा जा रहा है, अब सवालों के घेरे में

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, पर तकनीकी खामियों का आरोप लगाया गया है। एक्सप्रेसवे की स्टोन मस्टिक एस्फाल्ट (SMA) परत, जो सड़क की मजबूती का आधार मानी जाती है, उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ठेकेदारों और एनएचएआई अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

गडकरी का बयान:

"गुणवत्ता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और एनएचएआई अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।"

अब सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी में चूक हुई है? क्या यह खामियां भविष्य में सड़क हादसों का कारण बन सकती हैं?

गडकरी के अनुसार, देश में हर साल 1.68 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर सवाल और गंभीर हो जाते हैं।

गडकरी का बयान:

"हम सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपये सड़क हादसों को कम करने में खर्च किए जाएंगे।"

क्या दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई ये खामियां सरकार की छवि पर असर डालेंगी? क्या इसे जल्द सुधारने के कदम उठाए जाएंगे? या फिर यह एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो सवालों के घेरे में रहेगा?

आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें बताएं।

एफएनजी एक्सप्रेसवे: गाजियाबाद और गुरुग्राम को 45 मिनट में जोड़ने वाली नई राह

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में यातायात को सुगम बनाने के लिए फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (FNG) एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद को गुरुग्राम से जोड़ते हुए यात्रा समय को 2-3 घंटे से घटाकर लगभग 45 मिनट तक सीमित करेगा, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ होगा।

प्रमुख विशेषताएं और लाभ:

- सुगम यातायात:

6-लेन का यह एक्सप्रेसवे उच्च यातायात क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो भीड़भाड़ को कम करेगा।

- आर्थिक विकास:

बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर व्यापार और रियल एस्टेट क्षेत्रों में।

- सुरक्षा में सुधार:

आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के साथ, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

हालांकि, भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक चुनौतियों के कारण परियोजना में कुछ देरी हुई है। फिर भी, यह एक्सप्रेसवे NCR के शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे में तकनीकी खामियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे में तकनीकी खामियों के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, और दोषी ठेकेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी।

खामियों की पहचान और संभावित कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में एक्सप्रेसवे की एसएमए (स्टोन मेस्टिक एस्फाल्ट) परत में खामियां पाई गई हैं, जो टायरों के दबाव से प्रभावित हो रही हैं। गडकरी ने कहा कि दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा पर जोर

गडकरी ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सरकार 40,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि देश में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लगभग 1.68 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं।

टोल नाकों की समाप्ति की योजना

गडकरी ने टोल नाकों की समस्या को समाप्त करने का वादा किया है। अगले संसद सत्र से पहले नई तकनीक लागू की जाएगी, जिसके तहत वाहन बिना रुके टोल चुकाएंगे, और टोल वसूली वाहन की यात्रा के आधार पर होगी।

इन कदमों से सरकार की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

ऑटो पाट्र्स इंडस्ट्री पर चौतरफा मार, क्या केंद्र सरकार से मिलेगी राहत?

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो पाट्र्स इंडस्ट्री बढ़ती लागत और टैक्स की मार के बीच बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। स्टील पर 25 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव से भी इंडस्ट्री में चिंता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ने से भी ऑटो पा ट्र्स निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। उनका मानना है कि ई-वाहनों के आने से ऑटो पा ट्र्स उद्योग सिमट जाएगा।

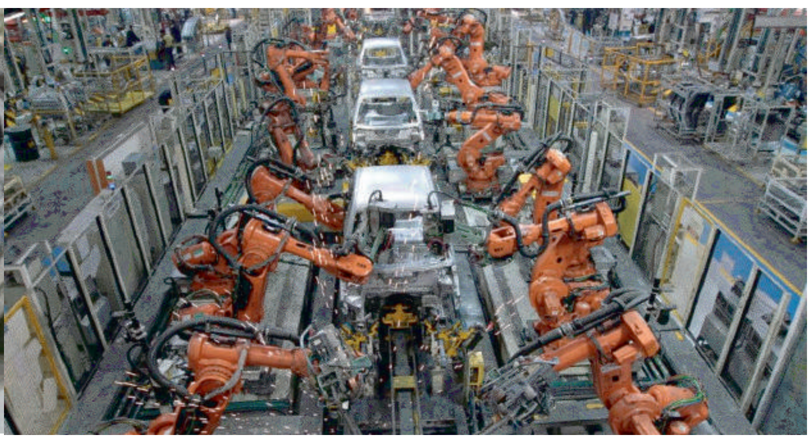

लुधियाना। देश का ऑटो पाट्र्स उद्योग रोजगार को लेकर अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। लगभग 57 अरब डॉलर के आसपास का कुल घरेलू आटो उपकरण उद्योग चौतरफा संकट से गुजर रहा है। बढ़ती लागत और टैक्स की मार के बीच संसाधनों की कमी के कारण ऑटो पाट्र्स उद्योग बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है।

ऊपर से केंद्र सरकार की ओर से स्टील पर 25 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव से उद्योग चिंता में पड़ गया है, क्योंकि इस उद्योग का कच्चा माल स्टील है। ऐसे में ऑटो पाट्र्स उद्योग को आगामी आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं।

उद्यमियों का कहना है कि केंद्र सरकार स्टील की कीमतों को स्थिर रखने के उपाय करे और स्टील नियामक प्राधिकरण बनाई जाए, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार स्टील की कीमतें कम से कम तीन महीने तक स्थिर रखे ताकि वह उत्पादन को लेकर बेहतर प्लानिंग की जा सके।

कंपनियां रोजाना नए मॉडल ला रही हैं। उनमें कम से कम पांच साल तक नए पाट्र्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए रिप्लेसमेंट मार्केट 60 प्रतिशत खत्म हो गया है। इसका असर भी आटो पाट्र्स उद्योग पर हो रहा है। सरकार को पाट्र्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत करनी चाहिए। प्री-बजट मेमोरेंडम में इन बातों का उल्लेख अपेक्स चैंबर करेगा।

रजनीश आहूजा, प्रेसिडेंट, अपेक्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

ई-वाहन इंडस्ट्री ने बढाई चिंता

भले ही केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ऑटो पाट्र्स निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। उनका मानना है कि ई-वाहनों के आने से आटो पाट्र्स उद्योग सिमट जाएगा। मौजूदा वाहनों के इंजन में दो हजार से अधिक मूविंग पाट्र्स लगते हैं, जबकि ई-वाहन में 20 से अधिक ही मूविंग पाट्र्स लग रहे हैं।

साथ ही, अत्याधुनिक वाहनों में उच्च गुणवत्ता के पुर्जे आने से वैकल्पिक बाजार भी लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में आटो पाट्र्स उद्यमी भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। पंजाब में आटो पाट्र्स उद्योग से जुड़ी दो हजार से अधिक इकाइयां हैं और इनमें वार्षिक 10 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार हो रहा है।

हाल ही में सरकार ने स्टील पर 25 प्रतिशत ड्यूटी लगाने का जो प्रस्ताव रखा है, वह आटो पाट्र्स उद्योग के लिए बड़ा संकट है। केंद्र सरकार को ड्यूटी लगाने से पहले इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान पर ध्यान देना चाहिए। इससे ऑटो पाट्र्स उद्योग में लागत बढ़ेगी और यह चिंता का विषय है।

गुरपरगट सिंह काहलों, अध्यक्ष, ऑटो पा ट्र्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

प्रतिस्पर्धा में स्थानीय उद्योग टिक नहीं पा रहा

संसाधनों की कमी के कारण ऑटो पाट्र्स उद्योग बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा चीन से आयात हो रहे उत्पादों को लेकर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। 25 प्रतिशत से अधिक पाट्र्स चीन से आयात हो रहे हैं, जबकि 60 प्रतिशत तक आटो एसेसरीज विदेश से आ रही हैं। कीमत की प्रतिस्पर्धा में स्थानीय उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में ऑटो पाट्र्स सेक्टर की मजबूती के लिए न केवल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बल्कि विशेष आर्थिक जोन की भी दरकार है।

ऑटो पाट्र्स उत्पादकों का कहना है कि उन्हें वैश्विक बाजार में जहां कड़ी चुनौतियां मिल रहीं हैं, वहीं बढ़ते आयात के चलते घरेलू मार्केट में भी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस घटती हिस्सेदारी को बचाने के लिए विकास एवं संशोधन केंद्र (आरएंडडी सेंटर) सहित तकनीकी अपग्रेडेशन आवश्यक हो गया है।

सरकार से क्या हैं ऑटो पाट्र्स इंडस्ट्री की उम्मीदें?

अगले 10 वर्षों में ऑटोमोबाइल पर टैक्स में कटौती से भारत का आटो उद्योग वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उद्यमी चाहते हैं कि उनके उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाए ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डटे रह सकें। उद्योग को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने, ईज आफ डूइंग बिजनेस को सही तरीके से प्रोत्साहित करने और उद्योग को जीएसटी रिफंड समय पर मिलने का इंतजाम किया जाए।

देश में ऑटो पा ट्र्स उद्योग की स्थिति

57 अरब डॉलर के आसपास है घरेलू ऑटो उपकरण उद्योग का कुल कारोबार।

21.2 अरब डॉलर के ऑटो उपकरणों का होता है निर्यात, 50 लाख लोग कार्यरत हैं।

7.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है देश की जीडीपी में आटो उपकरण उद्योग की।

200 अरब डॉलर का हो जाएगा आटो उपकरण उद्योग 2026 तक।

प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया: महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 'बीमा सखी योजना' का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

'बीमा सखी योजना' का उद्देश्य और लाभ:

- **महिला सशक्तिकरण:** यह योजना महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर देती है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकती हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं।
- **रोजगार सृजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- **आत्मनिर्भरता:**

महिलाएं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगी।

प्रधानमंत्री का संबोधन:

उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ₹महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। 'बीमा सखी योजना' महिलाओं को आत्मनिर्भर

बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

कार्यक्रम की तैयारियां:

इस अवसर पर लगभग एक लाख महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सैनी ने भी कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

भविष्य की योजनाएं:

प्रधानमंत्री मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी, जो क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।

'बीमा सखी योजना' महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत से एलआईसी बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना के तहत महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान हर महीने 7 हजार से 5 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। साथ ही पॉलिसी कराने पर कमीशन भी दी जाएगी।

बेंगलुरु में सैंडविच बेचकर फ्रांस का यह शख्स कमा रहा करोड़ों रुपये, कभी पढ़ाई के लिए आया था इंडिया

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस योजना में कोई भी 10वीं पास महिला अप्लाई कर सकती है। इसके लिए उम्र सीमा भी रखी गई है। 18 साल से 70 साल के बीच की कोई भी महिला इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के लिए अपनी निकटतम ब्रांच जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें।

अप्लाई करने से पहले एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और 10वीं पास के सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी।

कौन नहीं कर सकता अप्लाई?

अगर कोई शख्स पहले से ही एलआईसी एजेंट या एम्प्लॉई है तो उसका रिलेटिव (पति/पत्नी, बच्चे, पैरेंट्स, भाई-बहन आदि) इस योजना के तहत अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही एलआईसी का रिटायर्ड कर्मचारी या कोई पूर्व एजेंट या मौजूदा एजेंट भी इस योजना के तहत अप्लाई नहीं कर सकता।

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस योजना के तहत महिलाओं को एजेंट बनाने की ट्रेनिंग तीन साल तक दी जाएगी। इस दौरान उन्हें कुछ स्टाइपेंड यानी सैलरी भी दी जाएगी।

पहले साल 7 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे।

दूसरे साल में हर महीने 6 हजार रुपये दिए जाएंगे।

तीसरे साल में हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।

कमीशन भी मिलेगी

ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को सैलरी के अलावा कमीशन भी मिलेगी। यह कमीशन एलआईसी पॉलिसी कराने पर दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को पॉलिसी कराने का कुछ टार्गेट मिल सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो महिलाएं टार्गेट पूरा करेंगी उन्हें सैलरी और कमीशन के अलावा बोनस भी मिलेगा।

कितनी महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग?

'बीमा सखी योजना' के तहत एक साल में पूरे देश में दो लाख महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के पहले फेज में 35 हजार महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद 50 हजार और महिलाओं को योजना के अंतर्गत रोजगार मिलेगा।

तीन साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद महिलाएं एलआईसी एजेंट के तौर पर काम कर सकेंगी। साथ ही जो महिलाएं यानी बीमा सखियां ग्रेजुएट होंगी, उन्हें एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी मौका मिलेगा।

बीमा सखी योजना: ग्रामीण महिलाओं को बनायेगी सशक्त

भारत के प्रधानमंत्री 9 दिसम्बर 2024 को पानीपत से महिलाओं के लिए 'बीमा सखी' योजना शुरू की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान भी शुरू किया था। बीमा सखी योजना का उद्देश्य बीमा के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देता है और पूरे भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाता है। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। यह अपनी लड़ाइयों के लिए जाना जाता है और अब भारत में महिला सशक्तिकरण पहलों का केंद्र बिंदु है।

–प्रियंका सौरभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसम्बर को पानीपत का दौरा करेंगे और ₹बीमा सखी योजना₹ शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, महिलाएँ जीवन बीमा निगम की एजेंट बनेंगी, जिससे वे बीमा बेच सकेंगी और आय अर्जित कर सकेंगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। ₹बीमा सखी योजना₹ महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जो महिलाओं के लिए बीमा कवरेज को बढ़ावा देती है। यह योजना महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना है।

यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं को बीमा उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होगी, जो कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। इस सहायता का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। इस लॉन्च से महिलाओं के सशक्त होने की उम्मीद है। यह लैंगिक समानता के बारे में एक मज़बूत संदेश भेजेगा। यह पहल महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना है। 'बीमा सखी योजना' पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत चुनी गई महिलाएँ एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी और अपने समुदायों में बीमा सेवाएँ प्रदान करेंगी। इससे न केवल महिलाओं के लिए रोजगार पैदा होगा बल्कि वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से गहरा नाता है, अक्सर वे इसे महत्त्वपूर्ण पहलों के लिए लॉन्चिंग ग्राउंड के रूप में चुनते हैं। 2015 में पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' आंदोलन की शुरुआत सहित मोदी के अभियानों के साथ राज्य का इतिहास महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए एक मिसाल क़ायम करता है। महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान देने के लिए जाना जाने वाला हरियाणा एक बार फिर सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की राज्य की विरासत को और मज़बूत करेगी। 'बीमा सखी योजना' राज्य की सफल महिला-केंद्रित नीतियों के पोर्टफोलियो में शामिल होगी और समावेशी विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाएगी। 'नारी शक्ति' पर सरकार के ज़ोर को लोकसभा में पारित 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' जैसे प्रयासों के माध्यम से मज़बूत किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया।

बीमा सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रगतिशील पहल है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह पहल वित्तीय सेवाओं में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करते हुए स्थायी आजीविका बनाने का प्रयास करती है। इस योजना से महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा में एकीकृत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। लैंगिक समानताः यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बीमा सखी जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। एक स्थिर आय और करियर पथ प्रदान करके, कार्यक्रम कमजोर समुदायों की महिलाओं का उत्थान करना चाहता है।

पात्र महिलाओं को योजना के बारे में सूचित करने के लिए प्रभावी संचार रणनीतियाँ आवश्यक हैं। योजना की सफलता के लिए वेतन और कमीशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। बीमा क्षेत्र में अपनी भूमिका को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए महिला एजेंटों के लिए एक मज़बूत सहायता प्रणाली का निर्माण करना। आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं कक्षा की होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं और महिलाओं को ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों की निवासी होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को बीमा सखी के रूप में तैयार करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रमाणन प्रदान किया जाता है। एक निश्चित मासिक वेतनः पहले वर्ष में 7, 000, दूसरे में 6, 000 और तीसरे वर्ष में 5, 000 और बेची गई बीमा पॉलिसियों पर कमीशन के माध्यम से अतिरिक्त आय मिलेगी।

आयोगों और नीति-सम्बंधी अपडेट की निगरानी के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए नियमित कार्यशालाएँ। देश भर में 35, 000 महिलाओं को शामिल करने की प्रारंभिक योजना। हरियाणा का पानीपत, महिला सशक्तिकरण पर अपने ऐतिहासिक ज़ोर के कारण इस योजना का लॉन्चपैड है। आधिकारिक या नामित सरकारी पोर्टल पर जाएँ। व्यक्तिगत विवरण और वैध संपर्क जानकारी का उपयोग करके एक खाता बनाएँ। सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। आईडी प्रूफ, शैक्षिक प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदनों की समीक्षा की जाती है। स्वीकृत होने के बाद, उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड तक पहुँच प्राप्त होती है। 'बीमा सखी योजना' 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'नमो दीदी' कार्यक्रमों की सफलता के बाद, महिला-केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के पीएम मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका निरंतर प्रयास समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और विधायी परिवर्तनों में स्पष्ट है।

बीमा सखी योजना वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाकर, यह योजना न केवल उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करती है बल्कि उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भी एकीकृत करती है। कार्यक्रम की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन और हितधारकों से निरंतर समर्थन पर निर्भर करती है।

–प्रियंका सौरभ

बीमा सखी योजना 2024 - ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होगी

बीमा सखी योजना रेवड़ी से कोसों दूर,कौशलता के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने सटीक योजना है –एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत की बौद्धिक क्षमता कार्यकुशलता की प्रतिष्ठा को, रेवड़ी योजनाओं के प्रहार से हमला किया जा रहा है, या यूं कहें कि रेवड़ी प्रचलन बौद्धिक क्षमता को जंग लगाने का काम कर रहा हैक्योंकि स्वाभाविक है जिसको घर बैठे डीबीटी से पैसा मिल जाए 5 किलो प्रति मेंबर अनाज और परिवार को 1 किलो दाल मिल जाए तो वह अपना दिमाग क्यों खापाएगा इसका सटीक उदाहरण मैंनें प्रैक्टिकल देखा कि झाड़ के पत्तों की पत्तल बनाने वाली एक महिला कारीगर से मैंने जो पत्तल 40-50 रुपए बंडल मिलती थी, वह 150 रुपए बंडल देने की बात मैंने कही तो भी,उन्होंने बनाने से इंकार किया क्योंकि उसे लाडली बहन योजना से 1500 रूपए प्रतिमाह व राशन का अनाज मिलने की बात कही तो स्वाभाविक रूप से वह पत्तल बनाकर अपनी कौशलता में दिमाग खपाकर क्योंदिखाएंगे। यह बात करीब करीब हर क्षेत्र में महसूस किया जा रही होगी जिसका सुद्धारित रूप अब 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुई बीमा सखीयोजना से देखने को मिल सकता है, इस योजना को रेवड़ियों से काफी दूर रखा गया है, यांने ग्रामीण महिला मेहनत कर, घूम घूम कर, एलआईसी की बीमा पॉलिसी लेगी तो उसे उसका मेंहंनताना 7 से 21हज़ार तक होगा तथाप्रोत्साहन राशि 2100 अलग मिलेगी वो भी उसे प्रक्रिया से एलआईसी बीमा एजेंट बनना होगा। हालांकि बीमा एजेंट अभी कोई भी बन सकता है, यह कोई नई बात नहीं है परंतु यह विशेष योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए है व स्वाभाविक रूप से उन्हें अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें शासकीय कर्मचारियों की बीमा पॉलिसीयां दिलाई जाएगी,जिला स्तरपर उन्हें पॉलिसी मिलने का एक अदृश्य सपोर्ट किया जाएगा जिससे एक तीर से दो निशान होंगे, एक तो ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर पॉलिसी मिलेगी वह अपनी आय बढ़ाएगी, दूसरी ओर सरकारी प्रतिष्ठान एलआईसी को वित्त का साधन जनरेट होगा जो नेशनल लेवल पर विनियोग कर विज़न 2047 के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानें यह अप्रत्यक्ष रूप से विज़न 2047 में भरपूर कारगर सिद्ध होगा। चूँकि 9 दिसंबर 2024 को माननीय पीएम ने हरियाणा के पानीपत में दोपहर 2 बजे बीमा साखी योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है,यह योजना एलआईसी से संचालित की गई है, तो आए हुए पैसों से लॉन्ग टर्म विनियोग बढ़ेगा भारत के विकास के नए-नए अध्यायों के दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इसआर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,बीमा सखी योजना रेवड़ी से कोसों दूर बल्कि कौशलता के बलपर आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को जानने की करें तो, आज 9 दिसंबर को महिलाओं के लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है,इस योजना का नाम है बीमा सखी योजना,इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा एलआईसी की बीमा सखी योजना को शिक्षित महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत लोगों में वित्तीय समझ विकसित करने और बीमा की अहमियतसमझाने के लिए 10 वीं महिलाओं को 3 साल तक ट्रेंड किया जाएगा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए शुरू की गई इस योजना में महिलाओं को 7,000 से 21,000 रुपये तक हर महीने दिए जाएंगे. योजना की शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 7000 रुपये दिए जाएंगे, तो वहीं दूसरे साल में यह राशि 1000 रुपये कम करके 6000 रुपये कर दी जाएगी, तो तीसरे साल में 5000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। वहीं इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपये का अलग से योगदान दिए जाएगा तो साथ ही जो महिलाएं अपने बीमा के टारगेट पूरा करेंगी उन्हें अलग से कमीशन भी दिया जाएगा।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को महिला सशक्तिकरण व रोजगार की ओर कदम बढ़ाने की करें तो, जैसा इस स्कीम का नाम है बीमा सखी योजना यांने इसमें महिलाओं को बीमा से जुड़े काम के लिए सक्षम बनाया जाएगा,इस योजना के जरिए महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी नियुक्त किया जाएगा यांने उनको एलआईसी का एजेंट बनाया जाएगा।योजना में जुड़ने के बाद महिलाएं लोगों का बीमा कर सकेंगी। सरकार की इस स्कीम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को खासा लाभ होगा,ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार के मौके सामान्य तौर पर काफी कम होते हैं, ऐसे में सरकार की इस स्कीम से इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।माननीय पीएम नें सोमवार 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत से इस योजना का उद्धघाटन किया।भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों के लिए सरकार की अलग-अलग योजनाएं होती हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास करती रहती है महिलाओं के हित के लिए भी सरकार की कई योजनाएं होती हैं।

साथियों बात अगर हम बीमा सखी योजना को समझने की करें तो, केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है,इसी कड़ी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना लाई है।इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश महिलाओं के सशक्त बनाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाना है पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि 'बीमा सखी योजना' भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक पहल है। बीमा सखी योजना के जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 से 70 साल की उम्र की महिलाओं के सशक्तीकरण को बल मिलेगा। इस योजना के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और वजीफा दिया जाएगा।एलआईसी एजेंट से लेकर डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और ग्रेजुएट बीमा सखियों को एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा।पीएम नें भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किया, योजना के पहले फेज में 35 हजार महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर रोजगार दिया जाएगा। बाद में 50 हजार और महिलाओं को योजना में लाभ दिया जाएगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बीमा सखी योजना 2024 - ग्रामीण महिलाओं कोआत्मनिर्भर बनने में मील का पत्थर साबित होगी।बीमा सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार के अवसर बढ़ाकरआर्थिक सपोर्ट से उनका जीवन

मेरे लिए पटपड़गंज शिक्षा क्रांति का दिल था, अब यही काम जंगपुरा में सबके साथ मिलकर करने को तैयार हूं : मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज विधानसभा के बजाय जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा सोमवार को अपने उम्मीदवारों की जारी दूसरी सूची में मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल है। जंगपुरा से टिकट की घोषणा होने पर मनीष सिसोदिया ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार,के है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। इस दौरान उन्होंने पटपड़गंज विधानसभा के साथियों और जंगपुरा विधानसभा के वालेंटियर्स को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने सबके साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है।

मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। पटपड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। जब अवध ओझा जी पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी, तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटपड़गंज से बेहतर सीट कोई हो ही नहीं सकती। एक और शिक्षक को पटपड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मैं अब जंगपुरा में सबके साथ मिलकर वही काम करने को तैयार हूँ, जो पटपड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है। पटपड़गंज से जंगपुरा तक, मेरा संकल्प अडिग है: दिल्ली को और बेहतर बनाना। आपका भरोसा मेरी ताकत है। जय हिंद।

मनीष सिसोदिया का जंगपुरा के वालेंटियर्स को संदेश

इसके बाद मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा के वालेंटियर्स के नाम संदेश देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी ने मुझे आपकी विधानसभा जंगपुरा से चुनाव लड़ने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। यह केवल चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का संकल्प है कि जंगपुरा का हर बच्चा बेहतरीन शिक्षा पाए, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर गली और सड़क साफ-सुथरी हो, और हर परिवार को उनकी ज़रूरतें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार, बिना किसी बाधा के मिले। यह ज़िम्मेदारी मैं आपके साथ मिलकर ही निभा सकूंगा। आम आदमी पार्टी के बनने से लेकर अब तक मैंने देखा है कि जंगपुरा से पार्टी में एक से बढ़कर एक समर्पित वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने पार्टी के संघर्ष में अपनी मेहनत और योगदान से मिसाल कायम की है। यह आपका समर्पण ही है जिसने पूरी दिल्ली के लोगों के मन में पार्टी के लिए अथाह प्यार और भरोसा पैदा किया है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं पटपड़गंज विधानसभा के भाइयों और बहनों द्वारा तीन बार विधायक के रूप में चुना गया हूँ। मैं इसे अपनी राजनीति का जन्मस्थान मानता हूँ। लेकिन इस बार, जब अवध ओझा ने पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे पटपड़गंज, जो

> सिसोदिया ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं पटपड़गंज विधानसभा के भाइयों और बहनों द्वारा तीन बार विधायक के रूप में चुना गया हूँ। मैं इसे अपनी राजनीति का जन्मस्थान मानता हूँ। लेकिन इस बार, जब अवध ओझा ने पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे पटपड़गंज, जो शिक्षा की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है, से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी इस भावना ने मुझे गहराई से प्रभावित किया।

शिक्षा की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका है, से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी इस भावना ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैंने महसूस किया कि पटपड़गंज, जहाँ मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और तीन बार जीत हासिल की थी, वहाँ से लड़ने की उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईश्वर की कृपा और पूरे दिल्ली के लोगों और वालंटियर्स के प्यार और सम्मान से, मुझे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के वालंटियर्स और नेताओं ने यह प्रस्ताव दिया कि अगर अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनाव लड़ने के लिए अंतिम रूप दिया जाता है, तो मैं उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ूँ। यह आपके विश्वास और मेरे प्रति उनके स्नेह का प्रमाण है। लेकिन मैंने जंगपुरा के विधायक, मेरे दोस्त और छोटे भाई प्रवीण देशमुख के आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जंगपुरा आकर यहाँ से चुनाव लड़ूं। यह उनके बड़े दिल और आपके प्रति उनकी गहरी भावनाओं का प्रतीक है।

मनीष सिसोदिया का पटपड़गंज के साथियों के नाम संदेश

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अब एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने वाली शख्सियत ने हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया है। जब अवध ओझा ने पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया, तो उनके शब्द मेरे दिल को गहराई तक छू गए। उन्होंने कहा, ₹मैं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी शिक्षा की इस प्रयोगशाला पटपड़गंज से हो।₹ उनकी यह इच्छा और शिक्षा के प्रति उनका जुनून मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना। पटपड़गंज, जो मेरी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभिक और सबसे प्रिय स्थान रहा है, और जहाँ से तीन बार की जीत ने इसे शिक्षा और विकास की मिसाल बनाया, उसे छोड़ने का निर्णय आसान नहीं था। लेकिन शिक्षा के प्रति अवध ओझा की दृष्टि और समर्पण को देखते हुए मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सीट छोड़ने का नहीं, बल्कि पटपड़गंज और पूरे देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने का मौका है। मैंने पूरी दृढ़ता और गर्व के साथ यह निर्णय लिया कि पटपड़गंज की सीट अवध ओझा को सौंपी जाए, ताकि वे इसे नई ऊँचाइयों पर ले जा सकें। यह त्याग नहीं, बल्कि पटपड़गंज के भविष्य में, शिक्षा में, और हमारे देश के बच्चों के उज्ज्वल कल में मेरा योगदान है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो शिक्षा के क्षेत्र में गहरी समझ रखता है, हमारी पार्टी में जुड़कर चुनावी राजनीति में कदम रखता है, तो उनकी सफलता सुनिश्चित करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी मैं आप सब की तरफ़ देख रहा हूँ। एक बात और। पिछले दो साल न सिर्फ मेरे बल्कि आप सभी के लिये भी बहुत चैलेंजिंग थे। मुझे राजनीतिक साजिश के तहत 17 महीने जेल में रखा गया। पर जेल में मैंने सभी कठिनाइयों का सामना सिर्फ इस भरोसे पर किया कि बाहर मेरे परिवार और पटपड़गंज के लोगों की देखभाल के लिए आप मौजूद हैं। मुझे गर्व है कि इन कठिन परिस्थितियों में, मेरी गैर मौजूदगी में, आप में से हर एक ने मनीष सिसोदिया के लिए नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया बनकर काम किया है।

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि जैसे एक उम्र के बाद, बच्चा अपने घर से निकलकर, बाहर की दुनिया में जाता है कुछ नया करने, कुछ नया सीखने, मेरे लिये पटपड़गंज से निकलना कुछ इसी तरह का अनुभव है। पर ठीक उसी तरह, जैसे बच्चा कहीं भी जाए, उसका घर उसके दिल से दूर नहीं होता, वैसे ही पटपड़गंज मेरे दिल से दूर कभी भी नहीं हो सकता। पटपड़गंज मेरी आत्मा में बसा है और हमेशा रहेगा। आने वाले समय में चाहे मेरी पार्टी और सरकार में जो भी भूमिका हो, लेकिन आपसे मेरा रिश्ता मेरी आखिरी सांस तक अटूट रहेगा। आप के लिए मेरे दिल और घर के दरवाज़े हमेशा खुले रहेंगे।'

आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट में कहां से किसको मिला और कहां से किसका छीना टिकट

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। AAP ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी। आलम यह है कि पार्टी 18 सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काट चुकी है। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो एक से अधिक बार जीत दर्ज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने जिन 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, तीन सीटों पर मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अधिकतर हारी हुई सीटों पर जहां पुराने चेहरों पर दांव लगाया है तो जीते हुए कई उम्मीदवारों को इस बार मौका नहीं दिया गया है।

पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। पटपड़गंज की जगह उन्हें इस बार जंगपुरा सीट से उतारा गया है। वहीं, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान को मंगोलपुरी की बजाय मादीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है।

दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने शुक्रवार को दूसरी सूची जारी करते हुए कहा कि जनता से मिले फीडबैक और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का बंटवारा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 विधायकों की सीट बदली गई है तो अब तक 18 का टिकट काटा गया है। आने वाले दिनों में कई और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं।

इनसे छिन गई सीट

1.नरेला सीट से मौजूदा विधायक शरद कुमार की जगह दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है।

2.तिमारपुर सीट पर मौजूदा विधायक और विधानसभा में चीफ व्हिप दिलीप पांडेय की जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मौका दिया गया है।

3.आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा को इस बार मौका नहीं दिया गया है। पवन के स्थान पर इस बार नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद नेता मुकेश गोयल को उतारा गया है।

4.मुंडका से धर्मपाल लाकड़ा की भी छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह इस बार जसबीर काराला को उतारा गया है।

5.चादंनी चौक सीट से 2020 में आप के प्रह्लाद ने चुनाव जीता था। इस बार पुरनदीप सिंह स्वनेह को टिकट दिया गया है।

6.मादीपुर सीट से इस बार गिरीश सोनी का पत्ता कट गया है। उनकी जगह राखी बिड़लान को उतारा गया है, जो अब तक मंगोलपुरी से लड़ती रही हैं।

7.जनकपुरी से 2015 और 2010 में आप के राजेश ऋषि ने जीत हासिल की थी। इस बार उनकी जगह प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया है।

8. बिजवासन से 2020 में भूपिंदर सिंह जून ने जीत हासिल की थी। उनका टिकट काटकर अब सुरेंदर भारद्वाज को मौका दिया गया है।

9.पालम से 2015 और 2020 में भावना गौड़ ने शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। भवना की जगह जोगिंदर सिंह सोलंकी को मौका दिया गया।

10.जंगपुरा से प्रवीण कुमार को हटाकर मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है।

11.देवली से दो बार जीत चुके प्रकाश जारवाल की जगह इस बार प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया गया है।

12.त्रिलोकपुरी सीट से मौजूदा विधायक रोहित कुमार को हटाकर अंजना परचा को टिकट दिया गया है।

13.कृष्णा नगर से एसके बग्गा ने जीत हासिल की थी, अब विकास बग्गा को उतारा गया है।

14.शाहदरा से रामनिवास गोयल की जगह पदमश्री जितेंद्र सिंह शंटी को उम्मीदवार बनाया गया है।

15.मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस की जगह इस बार आदिल अहमद खान को टिकट।

16. बुराड़ी से ऋतुराज झा की जगह भाजपा से आए अनिल झा को टिकट मिला है।

17.सीलमपुर से अब्दुल रहमान की जगह चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया गया है।

18. मटियाला से गुलाब सिंह की जगह कांग्रेस से आए पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को टिकट दिया गया।

दिल्ली स्कूलों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल: दो प्रतिष्ठित स्कूलों को मिली बम धमकी

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

दिल्ली के दो प्रमुख स्कूल, डीपीएस आरके पुरम और जीडी गोयनका, सोमवार को बम धमाके की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना ने न केवल स्कूल प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया, बल्कि अभिभावकों और छात्रों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया।

घटना का विवरण

सोमवार सुबह दोनों स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। ईमेल में स्कूल परिसर में बम होने का दावा किया गया। इसके तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर स्कूलों की गहन तलाशी ली। हालांकि, तलाशी अभियान के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन यह घटना गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा करती है।

अभिभावकों में बढ़ा डर

इस घटना के बाद अभिभावक खासे चिंतित नजर आए। एक अभिभावक ने कहा, ₹हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं। हर बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।"

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और धमकी भरे ईमेल का स्रोत ट्रेस किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह शरारती तत्वों की हरकत हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

स्कूल सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

- क्या स्कूल परिसर में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं?
- क्या पुलिस और प्रशासन के पास ऐसी धमकियों से निपटने की पुख्ता योजना है?
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है?

पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

यह कोई पहली घटना नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा हो। पिछले कुछ वर्षों में कई बार स्कूलों को धमकी भरे ईमेल या कॉल्स मिली हैं, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हर बार अस्थायी समाधान तक ही सीमित रहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाना चाहिए। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, और नियमित सुरक्षा जांच जैसे उपाय अनिवार्य होने चाहिए। साथ ही, साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि इस तरह के ईमेल भेजने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके।

दिल्ली के स्कूलों में ऐसी घटनाएं न केवल बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि अभिभावकों और समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं। अब समय आ गया है कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और ठोस कदम उठाए। बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

पाकिस्तान की इशारे पर बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर हमले - पम्मा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले को लेकर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा रोष प्रकट किया है उन्होंने कहा, एक साजिश के तहत हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है यह सब पाकिस्तान व आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे, हत्याएं हो रहीं इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पम्मा ने कहा के जल्द ही नेशनल अकाली दल बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन करके रोष प्रकट करेगा। पम्मा ने कहा बड़े दुख की बात है। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां इन्हें रोकने की जगह केवल मूकदर्शक बनी हुई हैं। ऐसा लगता है यह किसी साजिश के तहत यह कार्य हो रहा है। ऐसे ही पहले पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करते रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले। इसी प्रकार यहां घटनाएं की जा रही है।

डोमा (DOMA) परिसंघ प्रतिनिधि संभल नहीं जा सके, भारी पुलिस बल ने रोका

शम्स आगाज़

नई दिल्ली। आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ (डोमा) की ओर से संभल के मरहूम परिवार से मिलने एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, जिसे पुलिस ने उ.प्र. और दिल्ली सीमा पर रोक दिया। प्रतिनिधि मंडल की ओर से नेतृत्व डोमा परिसंघ के चेयरमैन- डॉ उदित राज, राष्ट्र महासचिव- श्री शाहिद अली, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर - एडवोकेट सतीश सांसी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ए. पी. ख़ान छात्र नेता कुणाल, शकीलुर रहमान ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ़, मुजम्मिल हुसैन आई एन एल, मुकेश सैनी, शरीफ़ प्रधान, अब्दुल बारी खान, जांनिसार अख़्तर, मोहम्मद सलीम, सलीम खान आदि कर रहे थे।

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में आज नई दिल्ली से करीब 12 बजे 30 कारों का काफिला रवाना हुआ। जैसे ही गाजियाबाद सीमा पर पहुँचे, वहाँ खड़ी भारी पुलिस बल ने रोक दिया।इसके पहले श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक क़ाफ़िला संभल में मरहूम परिवार से मिलने जा रहा था, उसे भी रोका गया था।

उदित राज ने कहा कि दलित , ओबीसी, माइनॉर्टीज़ और आदिवासी परिसंघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। करीब 100 लोग आज इन्ही वर्गों से थे, अगर पीड़ित परिवार से मिलकर हाल-चाल जान लेते तो कौन सा सरकार संकट मे पड़ जाती। यह भी नहीं है कि हम राजनीतिक लोग हैं और इसका वोट बैंक पर असर पड़ता। सरकार इस्लामों फोबिया का भय दिखाकर मूल मुद्दे से देश के लोगों को भटकाना चाहती है। क्या हमारा कर्तव्य इतना भी नहीं बनता कि हम पीड़ित परिवार को मिलकर जानकारी लेते। यह लोक तंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? संविधान खतरे हैं। मुस्लिम और ईसाई पर हमले ज़्यादा तेज हुए हैं और इसके पीछे कुछ लोगों का राजनीतिक लाभ छुपा हुआ है।

डॉ. उदित राज जी ने आगे कहा कि अब न केवल राजनीतिक दल को लड़ना है बल्कि सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। जब बोलने की आज़ादी खत्म होती है या बेरोजगारी बढ़े और मंहगाई की मार पड़े तो आम नागरीक पर असर पड़ता है तो ऐसे में डोमा परिसंघ कैसे चुप रहा सकता है।

डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव शाहिद अली एडवोकेट ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया और किसी भी पार्टी के नेता और संगठन को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है,

प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वे चाहते हैं कि जितनी देरी होगी, भाजपा सरकार अपने मनसूबों में कामयाब हो जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि हम संभल में मुसलमानों पर हो रहे ज़ुल्म की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि संभल के मुसलमानों को सुरक्षा की जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय देते हुए दोषियों को सज़ा दी जाए।

नीरज बवाना और नवीन बाली गिरोह के 3 सदस्य दबोचे, दो हथियार तस्कर भी चढ़े हत्थे

पुलिस ने गैंगस्टरों और बंदूक तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नीरज बवानिया नवीन बाली और भाऊ गिरोह के तीन सदस्यों दबोचा है। इनके अलावा अलीगढ़ से दो हथियार तस्करों को भी अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 हथियार और 15 कारतूस जब्त किए गए हैं। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंगस्टरों और बंदूक तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नीरज बवानिया, नवीन बाली और भाऊ गिरोह के तीन सदस्यों और अलीगढ़ से दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

12 हथियार और 15 कारतूस बरामद

मुंगेर और अलीगढ़ मॉड्यूल से 12 हथियार और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें पिस्टल और एक आईओएफ रिवॉल्वर शामिल है। इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर और बलेनो कार भी जब्त की गई है। आरोपितों की पहचान महरौली निवासी सुबेग उर्फ शिब्बू, लाजपत नगर निवासी गौरव उर्फ सौरभी, जंगपुरा निवासी शरवन उर्फ हनी, अलीगढ़ का शोएब और अजीम के रूप में हुई है।

टीम का गठन किया गया

विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, दो दिसंबर को हवलदार सूर्या को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में शोएब नामक व्यक्ति द्वारा हथियारों की डिलीवरी के बारे में सूचना मिली थी। एसीपी नरेश सोलंकी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

वहीं, टीम ने मोहन एस्टेट कोआपरेटिव मेट्रो स्टेशन के पास एक भूरे रंग की बलेनो में शोएब को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक आईओएफ रिवॉल्वर और पिस्टल समेत पांच हथियार बरामद किए गए।

इसके अगले दिन तीन दिसंबर को दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व जिलों में छापेमारी के बाद लाजपत नगर से सुबेग उर्फ शिब्बू को गिरफ्तार करते हुए फॉर्च्यूनर कार जब्त की। इसके बाद जंगपुरा से शरवन उर्फ हनी को गिरफ्तार किया गया।

बरामद किए चार पिस्टल

वहीं, आगे कार्रवाई करते हुए टीम ने नेहरू नगर से गौरव उर्फ सौरभ को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से दो पिस्टल और देशी कट्टे बरामद किए। छह दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम ने अलीगढ़ के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी करते हुए नुमाइश मेला ग्राउंड से अजीम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चार पिस्टल बरामद किए।

उधर, पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार सभी आरोपित कई जघन्य अपराधों में शामिल हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और सशस्त्र डकैती शामिल हैं। आरोपितों ने बताया कि हथियारों को अलीगढ़, मुंगेर और बिहार के भागलपुर में तस्करी नेटवर्क से प्राप्त किया जाता था। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

गैंगस्टरों के लिए काम कर करते थे हथियारों की आपूर्ति

महरौली निवासी सुबेग उर्फ शिब्बू नीरज बवानिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो पहले हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, शस्त्र अधिनियम, आदि समेत सात मामलों में शामिल रहा है। वह दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली क्षेत्रों में फाइनेंसिंग का कारोबार करता है। 2018 में, फाइनेंसिंग कारोबार के दौरान लाजपत नगर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में पहली बार जेल गया था। जेल में वह नीरज बवाना और नवीन बाली के संपर्क में आया और उनके गिरोह में शामिल हो गया।

लाजपत नगर निवासी गौरव उर्फ सौरभ सुबेग का अधीनस्थ था। इससे पहले हत्या और हत्या के प्रयास समेत सात मामलों में शामिल रहा है। पहली बार 2011 में अमर कालोनी पुलिस थाने में हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ और करीब नौ साल जेल में रहा था। जेल में वह नीरज बवाना गैंग और शिब्बू के सदस्यों के संपर्क में आया और सिंडिकेट में शामिल हो गया।

भोगल के जंगपुरा निवासी शरवन उर्फ हनी कपड़ा व्यापारी से गैंगस्टर बन गया। गैंग की जीवनशैली से प्रभावित होकर पहले चार आपराधिक मामलों में शामिल रहा।

अलीगढ़ के सिविल लाइंस निवासी शोएब पहले एक हत्या के मामले में शामिल रहा। वह अलीगढ़ से दिल्ली में गिरोहों तक अवैध हथियारों की तस्करी करता था।

सर्दी का सितमः दिल्ली-एनसीआर में ठंड का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज
परिवहन विशेष

देशभर में मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है। वहीं, दक्षिण भारत में बारिश का कहर जारी है।

दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड का कहर

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के और गिरने की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का अनुमान

उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान लगाया गया है। विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि रबी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

तमिलनाडु, केरल, और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है।

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है

मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। ठंड और बारिश से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

पीएम मोदी को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात;

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में जयपुर से विशेष विमान से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचें। इसके बाद पीएम मोदी यहीं से हेलीकॉप्टर से पानीपत के लिए रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। बताया गया कि पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया।

साहिबाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने पहुंचे। राजस्थान से विमान से दोपहर करीब डेढ़ बजे गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। यहां से हेलीकाप्टर से पानीपत के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री का यहां पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। वहीं, सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम था। सोमवार को वह राजस्थान से विमान से दोपहर करीब डेढ़ बजे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे। यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री एवं साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी, शहर विधायक संजीव शर्मा, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, एमएलसी दिनेश गोयल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येन्द्र शिशोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी, जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल, मानसिंह गोस्वामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनसे संक्षिप्त चर्चा की।

शहर विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जानकारी ली। सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद हेलीकाप्टर से पानीपत के लिए रवाना हो गए।

सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व सोमवार सुबह नौ बजे से ही ड्यूटी पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। पानीपत तक के लिए कंटीजेंसी रूट भी तैयार किया गया था। इस पर भी पुलिसबल व पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास व छतों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन, एडीसीपी ट्रैफिक, प्रोटोकाल, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद समेत कई इंस्पेक्टर व ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को लगाया गया था। खुफिया विभाग भी सक्रिय रहा। पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। नगर निगम की ओर से विशेष साफ सफाई कराई गई थी और पानी का छिड़काव कराया गया।

फॉर्मर रजिस्ट्री होने पर ही किसान उठा सकेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ

सरकार ने फॉर्मर रजिस्ट्री शुरू की है। जिसमें क्षेत्र के सभी किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। किसान आधार कार्ड, खतौनी व मोबाइल नंबर से फार्म रजिस्ट्री से जुड़ सकता है।

गांव-गांव में लगाए जा रहे हैं शिविर

इसको लेकर तहसील प्रशासन की तरफ से गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। यदि कोई किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराता है तो वह प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।

देश में सबसे बड़ा होगा नोएडा एयरपोर्ट, कनेक्टविटी से लेकर प्रोजेक्ट के बारे में जानिए सबकुछ

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। सोमवार को एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार विमान उतरा यह ट्रायल के तौर पर था। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 6200 हेक्टेयर है। पहले चरण में 1334 हे. में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है। क्षेत्रफल और रनवे की संख्या में यह देश में सभी एयरपोर्ट को मात देगा। अप्रैल में एक रनवे के साथ एयरपोर्ट की शुरूआत होगी, लेकिन यात्रियों का सालाना संख्या बढ़ने के साथ रनवे की संख्या भी बढ़ती जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट पर कुल छह रनवे बनाए जाएंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 6200 हेक्टेयर है। पहले चरण में 1334 हे. में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। 3900 मी लंबे व साठ मीटर चौड़े रनवे के साथ अप्रैल में इसकी शुरुआत होगी। यात्रियों की संख्या सालाना 1.20 करोड़ होने पर दूसरा रनवे शुरू होगा। दूसरे चरण में 1365 हे. में एमआरओ के साथ एक रनवे बनाया जाएगा। इसकी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 30 किमी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। 40 एकड़ में एमआरओ बनेगा। सभी रनवे बनने के बाद 29.50 करोड़ यात्रियों की क्षमता हो जाएगी।

देश में पांच शीर्ष एयरपोर्ट में अभी हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलूरू, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा शामिल हैं।

एयरपोर्ट क्षेत्रफल रनवे की लंबाई

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद 5500 एकड़ 3800मी, 4260मी

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली 5106 एकड़ 2816मी, 3813मी, 4430मी, 4400मी

कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलूरू 4000 एकड़ दोनों 4000 मी

मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा 2132 एकड़ 3750 मी

डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा 1700 एकड़ 3430 मी

नोएडा एयरपोर्ट पर होंगे 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड दस एयरोब्रिज और 28 स्टैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने पर यात्रियों के लिए दस एयरोब्रिज होंगे। विमानों के लिए एयरक्राफ्ट स्टैंड 28 है। इनका 186 तक विस्तार किया जाएगा।

फ्यूल फार्म एयरक्राफ्ट के ईंधन के लिए हरियाणा के फरीदाबाद के पियाला से पाइप लाइन डाली गई है। इसकी लंबाई 35 किमी है। विकासकर्ता ने इसके लिए भारत पेट्रोलियम के साथ अनुबंध किया है। एयरपोर्ट परिसर में 33000 वर्गमीटर क्षमता का फ्यूल फार्म बनाया गया है।

2.5 लाख टन कार्गो क्षमता नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो का भी मुख्य केंद्र होगा। शुरुआत में एयरपोर्ट का सालाना कार्गो क्षमता 2.5 लाख टन होगी। चारों चरण पूरा होने पर इसकी कार्गो क्षमता 11.2 लाख टन होगी।

पर्यटन की बढ़ेंगी संभावनाएं

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतमबुद्ध नगर के साथ मथुरा, आगरा में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। मथुरा में धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के अलावा यमुना प्राधिकरण हेरिटेज सिटी बसाने जा रहा है। आगरा को भी एयरपोर्ट से फायदा होगा। दुनिया भर से पर्यटक यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिये मथुरा-आगरा सुगमता से आ जा सकेंगे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (Yamuna Authority Area) में फिल्म सिटी (Noida Film city) भी पर्यटन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए कब क्या हुआ?

2017 साइट क्लीयरेंस 2018 में भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति 1334 हे. जमीन पहले चरण के लिए अधिगृहीत की गई।

2020 में विकासकर्ता यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के साथ कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर।

2021 में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट 40 वर्ष के लिए एयरपोर्ट का लाइसेंस विकासकर्ता कंपनी को दिया गया।

2022 में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू। 3 साल दो माह 11 दिन में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। दो रनवे पहले चरण में बने।

2024 में सालाना सात करोड़ यात्री क्षमता।

अप्रैल तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगा एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Expressway) से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे (Link Expressway) का एलाइन्मेंट तैयार किया जा रहा है। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi Mumbai Expressway) से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए तीस किमी लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे (Green Field Expressway) अप्रैल से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इसका 21.5 किमी हिस्सा हरियाणा में और 8.5 किमी हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। बल्लभगढ़ के नजदीक यह दिल्ली मंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा।

यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर आठ लेन इंटरचेंज का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके जरिये एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। हाई स्पीड रेल, नमो भारत रेल से भी एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है।

आई युग में डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी चुनौती है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में डिजिटल अरेस्ट (साइबर स्कैम) आज एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रही है। सच तो यह है कि आज देशभर में साइबर क्राइम में तेजी आ रही है और बहुत से लोग जाने-अनजाने में इसके चक्कर में फंसे रहे हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज हमारे देश के सामने कई चुनौतियां हैं, मसलन आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, आर्थिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा व नार्को तस्करी, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच आज देश की सबसे बड़ी समस्या है-'बढ़ते साइबर अपराध।' यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से संचालित साइबर अपराध एक बड़े नियोजन अथवा कार्पोरेट ढंग में तब्दील होते जा रहे हैं। दरअसल, डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। वास्तव में, डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम यानी कि साइबर स्कैम में फोन करने वाले साइबर ठग कभी पुलिस अधिकारी बनकर, कभी सीबीआई बनकर, कभी नारकोटिक्स, तो कभी आरबीआई और दिल्ली या मुंबई पुलिस के अधिकारी बनकर किसी व्यक्ति से फोन पर पूरे आत्मविश्वास से बातचीत करते हैं। ऐसे साइबर ठग वॉट्सएप या स्काइप कॉल पर जब किसी व्यक्ति विशेष को कनेक्ट करते हैं तो ये फर्जी अधिकारी हमें एकदम असली से लगते हैं और हम इनके चक्कर में फंसकर अपना सबकुछ लुटा बैठते हैं। वास्तव में ये साइबर ठग किसी व्यक्ति विशेष को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये साइबर ठग यकीन दिलाते हैं कि हमारे साथ अथवा हमारे परिजनों के साथ कुछ बुरा हो चुका है या बुरा होने वाला है। इसमें सामने फोन पर बैठा व्यक्ति पुलिस अधिकारी की वर्दी में होता है, ऐसे में ज्यादातर लोग डर जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। बहुत बार डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठग हमें ठगी करते समय यह यकीं दिलाते हैं कि हमारे पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजों की खरीद हमारे द्वारा की गई हैं या फिर मनी लॉनड्रिंग की गई है। कई बार तो इन साइबर ठगों द्वारा यह तक दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और वे हमें फोन पर ही यह यकीं दिलाते हैं कि हमारे नाम से कोई पार्सल आया है, जिसमें ड्रग्स, नशीली या कोई प्रतिबंधित चीजें हैं। आज के समय में डिजिटल अरेस्ट से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी जागरूकता और सजगता हमें ऐसे साइबर ठगों से बचा सकती है। वास्तव में हमारी जानकारी, जागरूकता और सजगता ही डिजिटल अरेस्ट से बचने का उपाय है। वास्तव में यदि हमारे पास भी इस तरह की धमकी वाले फोन कॉल (डिजिटल अरेस्ट) आते हैं तो हमें इनसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। जब भी कोई कोई कॉल करके यदि हमें धमकाता है तो हमें यह चाहिए कि हम डरें कतई नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें, क्योंकि यदि हमने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। वास्तव में, ऐसे कॉल आने पर हमें यह चाहिए कि हम तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ई-मेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे। यदि किसी कारण हमने कोई कॉल रिसीव भी कर लिया है और यदि हमें कोई वीडियो कॉल पर किसी तरह की कोई धमकी भी देने लगे तो हमें यह चाहिए कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और इसकी शिकायत जल्द से जल्द पुलिस को करें। सबसे बड़ी बात किसी भी कीमत पर हम डरें नहीं और किसी भी माध्यम से पैसे तो बिलकुल भी ना भेजें। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज देश में डिजिटलाइजेशन होने के कारण जहां एक ओर बहुत लाभ हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कारण बहुत सी चुनौतियां भी आज उत्पन्न हुई हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में एवं एक कार्यक्रम में देश में बढ़ते साइबर अपराधों, डिजिटल अरेस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से पैदा हो रहे खतरों के बारे में अपनी चिन्ता जताई थी एवं इनसे सावधान व सजग रहने की बात कही थी। आज साइबर ठगी अपने पूर्ण परवान पर है। आज स्थिति यह है कि नित्य-रोज नये-नये साइबर ठगी के तरीके निकाले जा रहे हैं। साइबर ठग एआई तक का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह ठीक है कि एआई के आज बहुत से लाभ हैं जैसे कि यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनेक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है, क्रिएटिव वर्क को बढ़ावा दे सकता है, इसका अनुप्रयोग मनुष्यों की तुलना में अधिक परिशुद्धता प्रदान करने में सक्षम है, यह मानवीय सीमाओं के कारण होने वाली विफलताओं को कम करने में सहायक है, डेटा विश्लेषण पर लगने वाले समय को कम करता है, उत्पादन में उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करता है, अधिक तेज़ी से और अधिक कुशल निर्णय ले सकता है लेकिन इससे डीपफेक जैसे खतरे भी कहीं न कहीं जन्म ले रहे हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज डीपफेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनियाँ और वीडियो बनाये जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि एआई आज हमारे देश के लिए भी बेशक एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने पर यह एक बहुत बड़ा संकट भी है। वास्तव में, इससे निपटने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग के साथ ही हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। इसके लिए आज देश के सभी शहरों में डायल 100 को पूरी तरह से लागू किए जाने की जरूरत है। वास्तव में पुलिस के कार्यों में आज पूरी तरह से निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, तत्काल कार्रवाई और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अपराध के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे निपटने के लिए हमें विभिन्न आधुनिक उपकरणों से भी लैस होना पड़ेगा।

(लेख मौलिक और अप्रकाशित है।)
सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

3 साल, 2 माह और 11 दिन... नोएडा का एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार, यूपी में हवाई अड्डों की कितनी है संख्या

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंडिगो एयरलाइंस के विमान ने रनवे पर लैंडिंग की और जल तोप से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री केआर नायडू ने कहा कि यह देश के लिए प्रतिष्ठित परियोजना है। तीन साल दो महीने और 11 दिन में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और नोएडा 17वां होगा।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सोमवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। एयरपोर्ट पर पहले विमान की सफल लैंडिंग की गई। आसमान में डेढ़ घंटे उड़ान भरने के बाद इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) के वीटी आईएफआई विमान ने दोपहर करीब डेढ़ बजे नोएडा एयरपोर्ट के 3900 मीटर लंबे रनवे के पूर्वी दिशा को छुआ। इसके साथ ही पूरा एयरपोर्ट परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रनवे पर दौड़ते विमान को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए हर कोई आतुर हो उठा। वॉटर कैनन से विमान का नवनिर्मित एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री केआर नायडू और अन्य अधिकारियों ने नारियल फोड़ा और चालक दल के सदस्यों का स्वागत किया।

जांच के लिए जरूरी था ट्रायल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल सेवा (Noida Airport Commercial Services) शुरू करने से पूर्व एयरपोर्ट पर उपकरणों की तकनीकी, सुरक्षा आदि के पहलू से यह जांच अनिवार्य थी। पिछले बुधवार को महानिदेशालय नागर विमानन की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद एयरपोर्ट में विमान उतारने की अनुमति दी थी।

दिल्ली एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान

इंडिगो एयरलाइंस के वीटी आईएफआई विमान ने क्रू मेंबर के साथ दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport Delhi) से दोपहर करीब 12 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। दस मिनट में नोएडा एयरपोर्ट के एरियल स्पेस में पहुंचने के बाद करीब डेढ़ घंटे तक विमान ने उड़ान भरी और नेविगेशन समेत अन्य डाटा एकत्र किया।

दोपहर 1:30 बजे विमान ने रनवे की पूर्व दिशा में लैंडिंग की। रनवे के पश्चिम छोर से होकर विमान टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पहंचा, जहां वॉटर कैनन से पानी की बौछार कर उसका स्वागत किया गया।

हजारों कारीगर भी थे मौजूद

विमान के पहुंचते ही टर्मिनल बिल्डिंग लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। विमान की एक झलक देखने के लिए टर्मिनल के निर्माण कार्य में जुटे हजारों कारीगर एकत्र हो गए। उसमें से कई अपने मोबाइल में इस पल को कैद करने में जुट गए।

अधिकारियों ने विमान के साथ ली सेल्फी

केंद्रीय मंत्री केआर नायडू ने नारियल फोड़कर विमान और क्रू मेंबर का स्वागत किया। शासन के अधिकारियों से लेकर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (YEAPL), नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. नियाल (NIAL), एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स (TATA Projects) के अधिकारी विमान के साथ सेल्फी व फोटो खिंचवाने में मशगूल हो गए। दोपहर करीब 2:45 बजे विमान ने पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर रनवे पर दौड़ते हुए नोएडा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया।

नोएडा एयरपोर्ट एक प्रतिष्ठित परियोजना

नोएडा एयरपोर्ट पर पहले विमान की सफल लैंडिंग व टेकआफ से गदगद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री केआर नायडू ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट देश दुनिया के लिए प्रतिष्ठित परियोजना है। वैलिडेशन फ्लाइट की सफल लैंडिंग से यह साकार हुआ। दिल्ली एनसीआर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इज़ाफा हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है चार्जिंग की सुविधा, जिसके लिए देश के हर शहर में महत्वपूर्ण स्थानों पर, हर नेशनल और स्टेट हाईवे पर चार्जिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय के राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चार्जिंग स्टेशन का ब्योरा सदन में रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ईवी यात्रा पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसमें आप निकटतम पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। श्री नाइक के अनुसार 28 नवंबर 2024 तक देश भर में 25,202 चार्जिंग स्टेशन लगाये जा चुके हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 72,000 स्टेशन स्थापित करने का है।

पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को देखने के लिए ईवी यात्रा पोर्टल https:// evyatra.beeindia.gov.in पर जायें और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के मेन्यू में लोकेशन का नाम भरें। एंटर करते ही आपको गूगल मैप पर उस लोकेशन पर या उसके निकटतम स्थान पर ईवी चार्जिंग स्टेशन को दिखाएगा।

इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन से लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर सकते हैं, ताकि बीच रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं हो।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भारत के सबसे बड़े शो 'ईवीएक्सपो 2024' का करेंगे उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में 20 से 22 दिसंबर तक ईवीएक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय ई-वाहन कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। ईवीएक्सपो की शुरुआत 2015 से उद्घाटन करते आ रहे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा 21वें ईवीएक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी मौजूद रहेंगे।

ईवीएक्सपो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी है, जिसमें इको-फ्रेंडली दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार्गो के साथ-साथ, वाहनों के पुर्जे, आरएंडडी उपकरण, चार्जिंग स्टेशन उपकरण, लिथियम आयन बैटरियां और इस क्षेत्र से संबंधित उत्पाद और सेवाओं में आने वाले नित नए तकनीकी बदलाव और उन्नति को प्रदर्शित किया जाएगा।

यह ईवीएक्सपो इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्रीज के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें उन्हें अपनी नई तकनीकी को दिखाने एवं इसके अलावा इस सेक्टर में हो रहे नए शोधों और विकास एवं प्रौद्योगिकी बदलावों को भी जानने का मौका मिलेगा। ईवीएक्सपो 2024 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित एकमात्र एक्सपो है जो 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' और 'इको फ्रेंडली' वाहन उद्योग के लिए एक कुंजी की तरह है। यह एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में प्रदर्शकों, खरीदारों, वैश्विक नेताओं, ओपिनियन मेकर्स

और मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण इको सिस्टम बनाने में मददगार साबित होगी। इसमें रोजगार, व्यवसाय और निवेश के भी मौके बेशुमार हैं।

ईवीएक्सपो के को-फाउंडर एवं आयोजक अनुज शर्मा का कहना हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण की है और वायु प्रदूषण कि समस्या की अहम वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और उससे निकलने वाली धुआं है। ऐसा नहीं की वाहनों कि भविष्य में तादाद कम होगी, बल्कि और बढ़ेगी। ऐसे में ई-व्हीकल सबसे प्रभावी विकल्प के रूप में हमारे सामने है। ईवीएक्सपो एक ऐसा मंच है जिसका अहम मकसद देश में इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देना है। अनुज शर्मा ने आगे बताया कि इस एक्सपो में पर्यावरण अनुकूल वाहन प्रदर्शित की जायेंगी। इसके साथ-साथ यह एक्सपो रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराएगी।

इलेक्ट्रिक SUV Maruti eVitara टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, भारत में 2025 के शुरुआत में होगी लॉन्च

मारुति ईविटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस दौरान टेस्टिंग मॉडल में एलईडी डीआरएल के साथ हेडलाइट्स देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही इसमें क्लोज ग्रिल और अट्रैक्टिव स्पोर्टी फेशिया भी दिखाई दी। आइए जानते हैं कि Maruti eVitara Electric SUV किन फीचर्स के साथ भारत में आने वाली है।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में छोटी और बजट कारों के लिए जानी जाती है। कंपनी ने कई प्रीमियम पेशकश को पेश करके अपने पोर्टफोलियो को भारत में बढ़ाया है। वहीं, कंपनी जनवरी 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक SUV Maruti eVitara को पेश करने वाली है। इसे हाल ही में भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। आइए जानते हैं कि Maruti eVitara के टेस्टिंग मॉडल में क्या नया देखने के लिए मिला है।

टेस्टिंग मॉडल में क्या दिखा : हाल ही में इसे इटली के मिलान में पेश किया गया है। वहीं, इसके भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। ईविटारा को क्लोज ग्रिल और थोड़ी आक्रामकता के साथ एक अट्रैक्टिव स्पोर्टी फेशिया देखने के लिए मिला है। इसमें एलईडी डीआरएल के साथ हेडलाइट्स दी गई है, जो उसकी मौजूदगी को सड़क पर काफी अच्छी लगती है। इसके बम्पर में फॉग लाइट के साथ बुल बार के साइज में एक ओपनिंग शामिल है। इसमें चार्दिंग पोर्ट को सामने बाए तरफ क्वार्टर पैनल पर दिया गया है। मारुति ईविटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी की लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी, चौड़ाई 1,635 मिमी हो सकती है।

इसका व्हीलबेस 2,700 मिमी लंबा हो सकता है। वहीं, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 मिमी और कर्ब वेट 1,702 किलोग्राम से 1,899 किलोग्राम के बीच हो सकता है। इसके सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिले हैं। टेस्टिंग मॉडल में 18-इंच के व्हील देखने के लिए मिले हैं।

स्पेक्स और फीचर्स : मारुति ईविटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी में 49 kWh या 61 kWh बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है। इसे डुअल-मोटर 4WD ऑप्शन के साथ भी लाया जा सकता है। इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रिक मोटर 172 bhp की पावर और 189 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं, इसमें मिलने वाला 61 kWh बैटरी पैक 181 bhp की पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, वर्टिकल ओरिएंटेड AC वेंट, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लेटेस्ट कनेक्टिविटी सूट के साथ डुअल फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन और हाई-क्वालिटी मटीरियल देखने के लिए मिल सकता है।

भारत में कब होगी लॉन्च : सुजुकी ईविटारा पहले यूरोप और जापान में लॉन्च किया जा सकता है, इसके बाद भारत जैसे बाजारों में इसे लाया जा सकता है। वहीं, भारत में इसका उत्पादन फरवरी 2025 से शुरू होगा और इसे लॉन्च मई 2025 में किया जा सकता है। वहीं, इसके ग्लोबल प्रोडक्ट को भारत मोबिलीटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 में पेश किया जा सकता है।

काइनेटिक ग्रीन ने स्मार्ट टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध कराने के लिए जियोथिंग्स के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की प्रमुख निर्माता कंपनी काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की सहायक कंपनी और रिलायंस समूह के हिस्से जियोथिंग्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य उन्नत कनेक्टिविटी और एनालिटिक्स समाधानों को एकीकृत करके काइनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक वाहन पेशकशों के उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना है।

इस सहयोग के हिस्से के रूप में काइनेटिक ग्रीन अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल के लिए एक स्मार्ट टीएफटी-आधारित डिजिटल डिस्प्ले प्लेटफ़ॉर्म पेश करेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय नेविगेशन, इनकमिंग कॉल के लिए सूचनाएँ और आस-पास के चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी जैसी ज़रूरी सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य सवार की यात्रा की सुविधा और दक्षता को बढ़ाना है। यह नई तकनीक सवारों को महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, चाहे वे शहरी सड़कों पर नेविगेट कर रहे हों या लंबी यात्रा की योजना बना रहे हों।

इस प्लैटफ़ॉर्म में ब्लूटूथ और टेलीमैटिक्स-सक्षम सुविधाएँ भी शामिल होंगी जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए वाहन के कार्यों को प्रबंधित करने की अनुमति देती हैं। नेविगेशन, गति, बैटरी चार्ज स्थिति और खाली होने की दूरी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे उपयोगकर्ता के डिवाइस से उपलब्ध होगी, जिससे अधिक सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव मिलेगा। समाधान को जियो के हार्डवेयर और 4G कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिससे निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होगा।

यह सहयोग स्मार्ट वाहन प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए काइनेटिक ग्रीन के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

काइनेटिक ग्रीन की सह-संस्थापक और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा, ₹जियोथिंग्स के साथ हमारी साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और स्थिरता में नवाचार के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उन्नत सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना है जो ईवी सवारों के लिए समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है, और अधिक स्मार्ट और अधिक कनेक्टेड समाधान प्रदान करता है।₹

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष लोढ़ा ने कहा, ₹हम भारत में टिकाऊ गतिशीलता समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए काइनेटिक ग्रीन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। यह साझेदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने के हमारे साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।₹

दोनों कंपनियां कनेक्टेड और कुशल इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो भारत में टिकाऊ परिवहन के व्यापक लक्ष्य में योगदान दे रही हैं।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कर्नाटक में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 'टोयोटा यूथ कनेक्ट' किया लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने "टोयोटा यूथ कनेक्ट" कार्यक्रम शुरू किया है, जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से तीन सप्ताह की पहल है। कर्नाटक के सभी 30 जिलों में आयोजित इस कार्यक्रम ने 7,700 से अधिक युवाओं को लक्षित किया और छात्रों को ऑटोमोबाइल उद्योग में करियर के अवसरों से परिचित कराने के लिए 70 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग किया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना था, जिसमें उभरते हुए नौकरी बाजार की मांगों के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में उद्योग-विशिष्ट विशेषज्ञता और प्रशिक्षुता के अवसरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। टीकेएम ने पेशेवर कार्यस्थल संस्कृतियों के अनुकूल होने और उद्योग की जरूरतों से मेल खाने वाले कौशल हासिल करने के महत्व पर जोर दिया।

इस पहल के माध्यम से, टोयोटा का लक्ष्य कर्नाटक के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही ₹कौशल भारत₹ और ₹मेक इन इंडिया₹ जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देना है। शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए कंपनी का प्रयास व्यावहारिक शिक्षा के लिए एक मंच बनाने में मदद करता है, जिससे सामाजिक विकास और कार्यबल सशक्तिकरण के लिए इसकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वित्त और प्रशासन के कार्यकारी उपाध्यक्ष जी. शंकर ने कहा, ₹टोयोटा यूथ कनेक्ट कार्यक्रम भारत के युवाओं को विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में सफल करियर के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। युवा प्रतिभाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पोषित करके हम एक कुशल और आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान दे रहे हैं।₹ उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मविश्वास को प्रेरित करना, सीखने के लिए जुनून जगाना और तकनीकी क्षेत्र में करियर पथों पर स्पष्टता प्रदान करना है।

कार्यक्रम को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिनमें से कई ने प्रशिक्षुता के अवसरों और रोजगार कौशल के बारे में बेहतर समझ व्यक्त की। छात्रों ने कहा कि कार्यक्रम ने उन्हें अपने कैरियर के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में अधिक स्पष्टता दी।

इस पहल की सफलता के आधार पर, टोयोटा कर्नाटक में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देना जारी रखने की योजना बना रही है। टोयोटा यूथ कनेक्ट कार्यक्रम का अगला चरण आईटीआई के भीतर सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने और निरंतर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित होगा।

टोयोटा यूथ कनेक्ट के अलावा, टीकेएम अन्य शैक्षणिक पहलों में भी शामिल रहा है, जैसे कि टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (टीटीटीआई) और टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम (टी-टीईपी)। लंबे समय से चल रहे इन कार्यक्रमों ने आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया है, जो स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे प्रयासों के माध्यम से, टीकेएम का लक्ष्य एक कुशल कार्यबल के विकास में योगदान देना है जो भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन कर सके।

हुंडई मोटर इंडिया 2031 तक 600 ईवी फास्ट चार्जिंग स्टेशन करेगी स्थापित

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अगले सात वर्षों में पूरे भारत में लगभग 600 सार्वजनिक फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। 2024 के अंत तक हुंडई मोटर इंडिया के डीसी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क में 50 से अधिक स्टेशन शामिल होंगे, जो रणनीतिक रूप से राजमार्गों, शहरों और डीलरशिप पर स्थित होंगे।

कंपनी के मौजूदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने पहले ही लगभग 50,000 चार्जिंग सत्रों की सुविधा प्रदान की है, जिससे हुंडई और अन्य ब्रांडों के 10,000 से अधिक ईवी उपयोगकर्ताओं को 7.30 लाख यूनिट से अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है।

हुंडई मोटर इंडिया की चार्जिंग पहल को इसके मायहुंडई ऐप द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो चार्जज़ोन, स्टेटिक और शेल इंडिया जैसे सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करता है। यह साझेदारी देश भर में 10,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट तक पहुँच को सक्षम बनाती है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में निर्बाध यात्रा संभव हो पाती है।

कंपनी के फंक्शन हेड - कॉर्पोरेट प्लानिंग, जे वान रयू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईवे चार्जिंग सुविधाओं की कमी के बारे में ग्राहकों की आशंका अक्सर लंबी दूरी की ईवी यात्रा को सीमित करती है। इसे संबोधित करने के लिए, एचएमआईएल का लक्ष्य हुंडई मोटर कॉर्पोरेशन की वैश्विक ईवी और बैटरी तकनीक का लाभ उठाकर अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है।

अपने क्षेत्रीय प्रयासों के हिस्से के रूप में, एचएमआईएल ने 2027 तक राज्य में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 10 स्टेशन 2024 के अंत तक चालू हो जाएंगे। चेन्नई और तिरुवन्नामलाई में तीन चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं, और शेष जल्द ही खुल जाएंगे।

ये चार्जिंग स्टेशन भारत में निर्मित सभी चार पहिया ईवी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये सुविधाएं शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तराँ जैसे स्थानों पर रणनीतिक रूप से स्थापित की गई हैं, जहाँ 24x7 सीसीटीवी निगरानी और ऑन-साइट सहायता जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

कंपनी ने दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर, हैदराबाद-विजयवाड़ा, मुंबई-पुणे और पुणे-कोल्हापुर जैसे राजमार्गों सहित प्रमुख मार्गों को कवर करने के लिए अपने नेटवर्क का रणनीतिक रूप से विस्तार किया है। गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में भी एचएमआईएल के चार्जिंग स्टेशन हैं।

इन स्टेशनों में उन्नत विन्यास की सुविधा है, जिसमें DC 150 kW, DC 60 kW और DC 30 kW चार्जर शामिल हैं, जो विभिन्न ईवी चार्जिंग आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। आज तक, हुंडई मोटर इंडिया ने 4,061 से अधिक ईवी बेचे हैं, जिनमें हुंडई आयोनीक5 और हुंडई कोना जैसे मॉडल शामिल हैं। यह पहल भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को समर्थन देने तथा विश्वसनीय चार्जिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने के एचएमआईएल के प्रयास को दर्शाती है।

विजय गर्ग

आप अपनी नसों को स्थिर करने और खुद को शांत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? "बोर्ड परीक्षाएँ किसी भी अन्य परीक्षा की तरह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी पढ़ाई दूसरे स्कूल में होती है। इसलिए छात्रों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें रोजाना अपनाई जाने वाली सामान्य दिनचर्या पर कायम रहना चाहिए।"

सीबीएसई/आईसीएसई/स्टेट बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक: तनाव को कैसे दूर रखें?

जैसे-जैसे 15 फरवरी नजदीक आ रही है, बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हजारों छात्रों की चिंता बढ़ने और तनावग्रस्त होने की संभावना है। "क्या मैंने पर्याप्त तैयारी की है? क्या ऐसा कुछ है जो मुझसे छूट गया है? क्या मुझे उस विशेष विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए?" आपका मन ऐसे कई विचारों से घिरा रहेगा। आप कितना भी अध्ययन करें और विषयों का रिवीजन करें, संतुष्टि की भावना प्राप्त करना कठिन है। आप अपनी नसों को स्थिर करने और खुद को शांत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? "बोर्ड परीक्षाएँ किसी भी अन्य परीक्षा की तरह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी पढ़ाई दूसरे स्कूल में होती है। इसलिए छात्रों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें रोजाना अपनाई जाने वाली सामान्य दिनचर्या पर कायम रहना चाहिए।" अध्ययन युक्तियाँ तैयारी की रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं के लिए केवल आधा महीना शेष होने पर, आप समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं? "छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए अपना समय विभाजित करना चाहिए। जीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एमएचआर मलौट के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल विजय गर्ग कहते हैं, "उन्हें पहले पेपर के लिए और सबसे पहले आखिरी पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए।" वह सलाह देते हैं, ₹सुबह का समय पुनरीक्षण के लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि रिटेंशन बेहतर होता है और शरीर और दिमाग तरोताजा रहते हैं।₹ नोट बनाना एक प्रभावी तरीका है जो आपके काम आ सकता है। "छात्रों को मुख्य बिंदुओं के नोट्स तैयार करने चाहिए क्योंकि अंतिम समय में, पूरे पाठ्यक्रम को दोबारा शुरू करना संभव नहीं है। नोट्स उनके लिए स्मृति से शीघ्रता से याद करना आसान बनाते हैं।" एक अन्य परीक्षणित विधि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और नमूना पत्रों को हल करना है। "छात्र घर पर परीक्षा का अनुकरण कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें पेपर हल करने में कितना समय लग रहा है। परिणाम के आधार पर, वे अपनी गति और सटीकता में सुधार कर सकते हैं।

वे जितने अधिक सैंपल पेपर हल करेंगे, वे उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे," श्री गर्ग कहते हैं अपने बच्चे की सफलता में माता-पिता की भी अहम भूमिका होती है। उन्हें सहायक और उत्साहवर्धक होना चाहिए और छात्रों को आत्म-अनुशासन, आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे उसका मनोबल बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। समूह अध्ययन अध्ययन का एक लोकप्रिय तरीका है। लेकिन क्या यह हमेशा प्रभावी होता है? "हालांकि यह संदेह और अवधारणाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह याद रखने में मदद नहीं करता है। अंतिम पुनरीक्षण के लिए, स्व-अध्ययन सबसे अच्छा है," गर्ग कहते हैं। जीवनशैली युक्तियाँ परीक्षा के दौरान, छात्रों का तनाव स्तर आमतौर पर चरम पर होता है। इससे अत्यधिक खाना, नींद आने में कठिनाई आदि होती है। कोई इससे कैसे निपट सकता है? "छात्रों को हल्का आहार लेना चाहिए। इससे वे तरोताजा रहेंगे और पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आएगी। नाश्ते में हल्का भोजन जैसे दलिया या अनाज शामिल हो सकता है। फल और सूखे मेवे आवश्यक विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। जब भी छात्रों को भूख लगे या थोड़ी सुस्ती महसूस हो तो उन्हें अमरूद, सेब, केला आदि फलों का आहार लेना चाहिए। इसके अलावा, अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो, तो सूखे मेवे अपने पास रख सकते हैं," गर्ग कहते हैं काउंसिलिंग छात्रों को उनके तनाव से राहत दिलाने में मदद करने के लिए, सीबीएसई ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और प्रशिक्षित परामर्शदाता छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वेच्छा से आए हैं। किसी भी बोर्ड के छात्र उनसे जुड़ सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118004 है और यह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहता है। परीक्षा के दिन परीक्षा के दिन, यह आवश्यक है कि आप शांत और केंद्रित रहें। पेट में तितलियों का उड़ना स्वाभाविक है। सुनिश्चित करने के लिएताकि आपसे कुछ छूट न जाए, एक चेकलिस्ट तैयार करें। अपना घर छोड़ने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित वस्तुएं हैं: पानी की बोतल, अतिरिक्त पेन, रूलर, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, घड़ी और हॉल टिकट। यहां उन चीजों की एक चेकलिस्ट दी गई है जो आपको परीक्षा लिखते समय करनी चाहिए: शुरुआत में 15 मिनट का कूल-ऑफ पीरियड होता है, जिसमें आपको परीक्षा लिखने के लिए मिलने वाला समय शामिल नहीं होता है। इस समय का उपयोग प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने में करें। यद्यपि सलाह दी जाती है, फिर भी प्रश्नों का उत्तर उसी अनुक्रम/क्रम में देना आवश्यक नहीं है। जिन्हें आप जानते हैं उन्हें पहले हल करें, लेकिन उन्हें सही ढंग से नंबर दें। यदि आपके पास समय समाप्त हो रहा है, तो प्रश्न छोड़ने के बजाय उत्तर को अंकों में लिखें। आरेखों को ठीक से लेबल करें. अंत में, याद रखें कि हालांकि इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाते हैं तो यह दुनिया का अंत नहीं है। अनंत अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं।

कहानी : रोटी

दो -चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुऐ थे, वहाँ बातों -बातों में रोटी की बात चल गई..

तभी एक दोस्त बोला - ₹जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है?"

किसी ने मोटी, पतली तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया...

तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त... भावना और कर्म के आधार से रोटी चार प्रकार की होती है।"

पहली "सबसे स्वादिष्ट₹ रोटी ₹माँ की ₹ममता₹ और ₹वात्सल्य₹ से भरी हुई। जिससे पेट तो भर जाता है, पर मन कभी नहीं भरता।

एक दोस्त ने कहा, सोलह आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है।"

उन्होंने आगे कहा ₹हाँ, वही तो बात है।

दूसरी रोटी पत्नी की होती है जिसमें अपनापन और ₹समर्पण₹ भाव होता है जिससे ₹पेट₹ और ₹मन₹ दोनों भर जाते हैं।₹,

क्या बात कही है यार ?₹ ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं।

फिर तीसरी रोटी किस की होती है?₹ एक दोस्त ने सवाल किया।

"तीसरी रोटी बहू की होती है जिसमें सिर्फ ₹कर्तव्य₹ का भाव होता है जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है₹।

थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई।

"लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है ?₹ मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा-

"चौथी रोटी नौकरानी की होती है। जिससे ना तो इन्सान का ₹पेट₹ भरता है न ही ₹मन₹ तृप्त होता है और ₹स्वाद₹ की तो कोई गारँटी ही नहीं है", तो फिर हमें क्या करना चाहिये?

माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बना कर जीवन जिओ, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी ग़लतियाँ नज़रन्दाज़ कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा।

यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आयें तो भगवान का शुकर करो कि उसने हमें ज़न्दा रखा हुआ है, अब स्वाद पर ध्यान मत दो केवल जीने के लिये बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाये और सोचो कि वाकई, हम कितने भाग्यशाली है

विजय गर्ग

मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव का एक साल... चाणक्य बने या चुनौतियों से घिरे

पवन वर्मा

समय, काल, परिस्थिति पर किसी का वश नहीं चलता, ठीक एक साल पहले यानि दिसंबर के शुरूआती दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे मध्यप्रदेश की पूरी राजनीति उनके आसपास ही सिमटी हुई थी, लेकिन उसी दिसंबर में वक्त बदला भाजपा के विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले मोहन यादव पांचवी पंक्ति में बैठे थे, चंद मिनट बाद वे प्रथम पंक्ति के सबसे अहम किरदार हो गए। इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के कद के समान कोई दूसरा नेता नहीं था। मुख्यमंत्री की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान के साथ कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों के नाम थे। इन सबके बावजूद मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज दिया गया। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने कई चुनौतियां थी। जिसमें सबसे पहली चुनौती अपने काम के बल पर सफलता की नई कहानी लिखने की थी। तो दूसरी तरफ चाणक्य बनकर राजनीति की आड़ी तिरछी चालों से मुकाबला करना था।

अब इस दिसंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस पद पर बने हुए एक साल हो रहा है। इस एक साल में उनके खाते में उपलब्धियां खूब आई तो राजनीति की चालों में वे विरोधियों के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी रहे और उनके वार भी झेलते रहे। वहीं अपनी कूटनीति और रणनीति से वे प्रदेश भाजपा के कई मजबूत नेताओं को एक निश्चित दायरे में सीमित करने में भी सफल रहे। विरोधाभास यह भी कि कई फैसलों में दिल्ली ताकतवर नजर आई तो कई फैसलों में अफसरशाही हावी दिखाई दी। डॉ. मोहन यादव ने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश भाजपा के ताकतवर नेताओं के कद्दावर कद के बीच में स्वयं को स्थापित करने की थी।

सबसे पहले उनके सामने चुनौती तब आई जब उनके मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय मध्य प्रदेश के दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बना दिया गया। इनके साथ ही प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे राकेश सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। हालांकि भाजपा में यह परम्परा नई नहीं थी, बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी भी सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही दिन से इस चुनौती से मोहन यादव जूझते रहे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह ने भी मुख्यमंत्री का साथ दिया और उनके कदम से कदम मिलाकर निर्णयों का स्वागत किया। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री इस चुनौती से वे उभरते दिखाई दे रहे थे लेकिन राजनीति सदैव परिवर्तन शील ही रहती है यह तब दिखाई दिया जब दिसंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने सड़कों को लेकर आए प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी। यानि दिग्गजों की इस चुनौती से मोहन यादव पूरी तरह से उभर नहीं सकें हैं।

सिमटते शिवराज सिंह

इधर मुख्यमंत्री बनने के बाद महज 6 महीने बाद ही शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बनकर दिल्ली चले गए। वे वहां केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए सुखद रहा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने

मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वे महिलाओं के भाई और मामा बन चुके थे। युवाओं में भी उनका क्रेज कम नहीं था। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के नाम और लोकप्रियता के आगे स्वयं को स्थापित करना भी कम चुनौती भरा नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं प्रदेश में लागू की। जिसमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में सक्रिय थे। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब चौहान केंद्रीय मंत्री बने तो मध्यप्रदेश में वे केवल विदिशा-रायसेन-सीहोर और देवास जिले तक यानि अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही सिमट गए हैं। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री के रुप में शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में अब खासे सक्रिय हो गए हैं।

संगठन में भी सफल रहे यादव

डॉ. मोहन यादव ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब संगठन में उनके समर्थकों की संख्या कम थी, उस वक्त संगठन के अधिकांश नेता शिवराज सिंह चौहान की ताारीफों के कसीदे गढ़ते थे लेकिन अब इनमें से अधिकांश नेता मोहन यादव के समर्थक हो गए हैं। इस मामले में वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से ज्यादा मजबूत माने जाने लगे हैं। संगठन के पदाधिकारी मोहन यादव के निर्णयों का खासा प्रचार कर, उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इस काम में लगभग पूरा संगठन मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करने लगा है। हालांकि केंद्रीय योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम-काज का प्रचार करने में ये पदाधिकारी उतने सक्रिय नहीं हैं, जितने डॉ. मोहन यादव की योजनाओं और कामकाज का प्रचार-प्रसार और तारीफ करते हैं।

अफसरों पर कभी भारी तो कभी कमजोर

मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के तेवर देख कर अफसर भी दंग थे। शाजापुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर किशोर कान्याल ने एक ड्राइवर को अपमानित कर दिया, इस पर मुख्यमंत्री ने उनका तबादला कर दिया। ऐसे ही कई उदहारण उन्होंने अफसरशाही में प्रस्तुत किए। इसी दौरान उन्होंने ऐसे अफसरों को फील्ड से हटाया जो लंबे समय से फील्ड में पदस्थ थे। इससे कई ऐसे अफसरों को मौका मिला जो कुछ वर्षो से उपेक्षा का शिकार सा महसूस कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसरों की पदस्थापना की। इन्हीं में से एक अफसर को मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन मुख्य सचिव का फैसला दिल्ली से ही तय हुआ माना गया। वहीं इसी दौरान उन्होंने किशोर कान्याल को श्योपुर जिले का फिर से कलेक्टर बना दिया, यानि उनके तेवर कान्याल को लेकर क्यों नरम हुए, यह सवाल खड़ा हो गया। दूसरी ओर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में मोहन यादव ने अपनी ताकत का अहसास करवाया और अपनी पसंद के कैलाश मकवाना को यहां पर पदस्थ किया। इसके साथ साथ चर्चाएं तो यह भी हैं कि अफसर मुख्यमंत्री के आदेशों में जमकर अडंगे लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सैकड़ों आदेशों को दबा दिया गया है।

उम्मीदें जो बाकी हैं

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. यादव का एक साल अच्छे से बीत गया, अब आने वाले वर्षो में उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद उन लाड़ली बहनों को होगी, जिन्हें पिछले साल से ही हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। यह राशि तीन हजार रुपए तक ले जाने का भाजपा का वादा है। अब इस राशि में कब बढ़ोतरी होती है, इस उम्मीद में प्रदेश में सवा करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं। इसमें आने वाले निवेश का भी लोगों को इंतजार है, बेरोजगारों को रोजगार का इंतजार है। राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ से कैसे छुटकारा मिलेगा इसका भी लोगों को इंतजार है।

कुल मिलाकर एक साल में डॉ. मोहन यादव प्रदेश में चुनौतियों से लगभग उभर चुके हैं और मजबूती से स्थापित हो गए हैं, अब दूसरा साल उनका शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय सरकार से भरपूर सहयोग मिलने से यह उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री का दूसरा साल पहले साल से बेहतर साबित होगा और उनके कार्यकाल में मध्यप्रदेश के नागरिकों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरपूर रहेगा।

अमर बलिदानी प्रफुल्ल चाकी जिनका सिर काटकर अदालत में पेश किया गया

जन्मदिन 10 दिसम्बर पर विशेष

हमारा देश क्रांतिकारियों की वीरगाथाओं से भरा पड़ा है।प्रफुल्ल चाकी देश के पहले ऐसे युवा और वीर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इस युवा क्रांतिवीर ने अंग्रेजों से घिरने पर अपने सिर में गोली मार ली और स्वयं को जीते जी देश के लिए बलिदान कर दिया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मुजफ्फरपुर का किंग्सफोर्ड बम कांड ख़ासा महत्व रखता है। यह कांड क्रांतिकारियों के अपमान के बदले के रूप में भी चर्चित है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके चलते गुलामी के इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा अलीपुर बम केस हुआ और बंगाल के क्रांतिकारियों के निर्भीक आत्मोत्सर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा पूरे देश में आग की तरह फ़ैल गई।

सन-1888 में 10 दिसम्बर के दिन जन्मे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रफुल्ल का जन्म उत्तरी बंगाल के जिला बोगरा के बिहारी गाँव (अब बांग्लादेश में स्थित) में हुआ था। जब प्रफुल्ल दो वर्ष के थे तभी उनके पिता जी का निधन हो गया। उनकी माता ने अत्यंत कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ और उनके अन्दर देश को स्वतंत्र कराने की भावना बलवती हो गई। इतिहासकार भास्कर मजुमदार के अनुसार प्रफुल्ल चाकी राष्ट्रवादियों के दमन के लिए बंगाल सरकार के कार्लाइस सर्कुलर के विरोध में चलाए गए छात्र आंदोलन की उपज थे।

वह सन-1907 का समय था। बंगाल को तत्कालीन लार्ड कर्जन ने विभाजित कर रखा था और मातृभूमि को प्रत्यक्ष माता का स्वरूप मानकर ₹वन्देमातरम्' गीत से उसकी वन्दना करने वाले युवक और छात्र-दल, जिनके नेता अरविन्द घोष और बारीन्द्र घोष थे, अपना घर-परिवार त्यागकर अंग्रेजों से जूझ रहे थे। 16-17 वर्ष के छात्र अंग्रेजों और उनके पिट्ठू सरकारी अधिकारियों पर प्रहार कर रहे थे। ये नवयुवक 'छात्र-भंडार' खोलकर नगरों में स्वदेश की बनी वस्तुएं बेचते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। अरविन्द घोष ने स्वयं ही मिदनापुर के सत्येन्द्र नाथ बसु जैसे युवकों को क्रांति की शिक्षा दी थी। मिदनापुर के मियां बाजार में किराए के मकान में एक अखाड़ा चलता था, जिसमें लाठी, तलवार चलाने के साथ ही बंदूक से लक्ष्य भेद और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाता था। यही अखाड़ा गुप्त क्रांतिकारी समिति के रूप में सक्रिय हुआ।

पूर्वी बंगाल के छात्र आंदोलन में प्रफुल्ल चाकी के योगदान को देखते हुए क्रांतिकारी बारीद्र घोष उन्हें कोलकाता ले आए जहाँ उनका सम्पर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से हुआ। उन दिनों सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल का राज्यपाल था जिसने लार्ड कर्जन की बंग-भंग योजना को क्रियान्वित करने में भरपूर उत्साह दिखाया था। फलतः क्रांतिकारियों ने इस अंग्रेज को मार देने का निश्चय किया। अरविन्द के आदेश से समिति के यतीन्द्रनाथ बसु, प्रफुल्ल चाकी के साथ दार्जिलिंग गए, क्योंकि वह राज्यपाल वहीं था परन्तु वहां जाकर देखा गया कि राज्यपाल की रक्षार्थ सख्त पहरा है और कोई उसके पास तक पहुंच नहीं सकता। अतः ये लोग लौट आए और यह योजना सफल नहीं हुई। उसे मारने का दूसरा प्रयास सन-1907 के अक्तूबर में भी हुआ, जब उसकी रेल को बम से उड़ाने गए अरविन्द घोष के भाई बारीन्द्र घोष, उल्लासकर दत्त, प्रफुल्ल चाकी और विभूति सरकार ने चन्दननगर और मानकुंड रेलवे मार्ग के बीच एक गड्ढा खोदकर उसमें बम रखा, परन्तु वह उस रेल मार्ग से गया ही नहीं। आगे उसी साल 6 दिसम्बर को भी बारीन्द्र घोष, प्रफुल्ल चाकी और दूसरे कई साथियों को लेकर खड्गपुर गए और नारायण गढ़ जाने वाले मार्ग से एक मील दूर खड्गपुर के रेल मार्ग पर एक सुरंग रात के 11-12 बजे के बीच लगायी किन्तु रेल के क्षतिग्रस्त होने पर भी वह राज्यपाल बच गया। 7 नवम्बर, 1908 को भी इसी एंड्रयू फ्रेजर को कलकत्ते के ओवरटून हाल के एक बड़े जलसे में क्रांतिकारी जितेन्द्र नाथ राय ने पिस्तौल से गोली मारने की चेष्टा की, पर 3 बार घोड़ा दबाने पर भी गोली न चलने से वह पकड़े गए और उन्हें 10 वर्ष की सजा मिली।

क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दण्ड देने के लिए कुख्यात कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को जब क्रांतिकारियों ने जान से मार डालने का निर्णय लिया तो यह कार्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। दोनों क्रांतिकारी इस उद्देश्य से मुजफ्फरपुर पहुंचे जहाँ ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भाँप कर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर भेज दिया था। खुदीराम मुजफ्फरपुर आकर महाता वार्ड स्टेट की धर्मशाला में दुर्गादास सेन के नाम से और प्रफुल्ल चाकी दिनेशचंद्र राय के छद्म नाम से ठहरे। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया एवं 30 अप्रैल 1908 ई० को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया जब वह बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। पर दुर्भाग्य से उस बग्घी में मिसेज कैनेडी और उसकी बेटी क्लब से घर की तरफ़ आ रहे थे। उनकी बग्घी का लाल रंग था और वह बिल्कुल किंग्सफ़ोर्ड की बग्घी से मिलती-जुलती थी। खुदीराम बोस तथा उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने उसे किंग्सफ़ोर्ड की बग्घी समझकर ही उस पर बम फेंक दिया था। देखते ही देखते बग्घी के

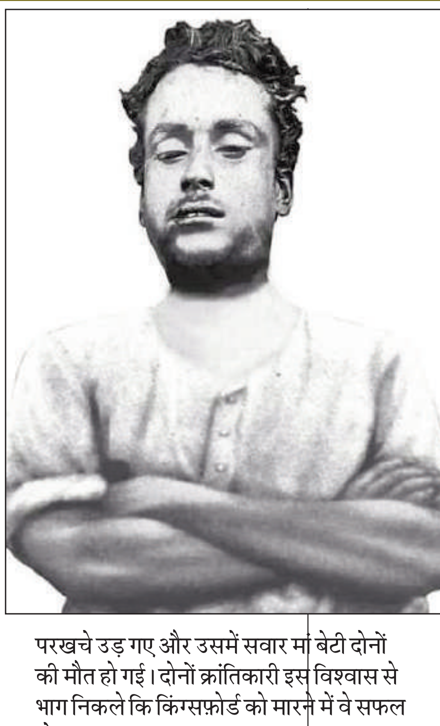

परखचे उड़ गए और उसमें सवार मां बेटी दोनों की मौत हो गई। दोनों क्रांतिकारी इस विश्वास से भाग निकले कि किंग्सफ़ोर्ड को मारने में वे सफल हो गए।

जब प्रफुल्ल और खुदीराम को ये बात पता चली कि किंग्सफोर्ड बच गया और उसकी जगह गलती से दो महिलाएं मारी गई तो वो दोनों दुखी और निराश हुए और दोनों ने अलग अलग भागने का विचार किया। खुदीराम बोस तो मुज्जफरपुर में पकडे.गए और उन्हें इसी मामले में 11 अगस्त 1908 को फांसी हो गयी। उधर प्रफुल्ल चाकी जब रेलगाड़ी से भाग रहे थे तो समस्तीपुर में एक पुलिस वाले को उन पर शक हो गया और उसने इसकी सूचना आगे दे दी। जब इसका अहसास प्रफुल्ल को हुआ तो वो मोकामा रेलवे स्टेशन पर उतर गए पर तब तक पुलिस ने पूरे मोकामा स्टेशन को घेर लिया था।

1 मई 1908 की सुबह मोकामा में रेलवे की एक पुलिया पर दनादन गोलियाँ चल रही थी। जो लोग उस समय वहां रेलवे स्टेशन पर अपनी अपनी गाड़ियों का इन्तजार कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और जिसको जहाँ जगह मिली वहीं छुप गया। लगभग ढाई घंटे तक उस छोटे से रेल्वे स्टेशन पर गोलियां चलती रही और एक बहादुर जाबांज अपनी छोटी सी रिवाल्वर से उनका मुकाबला करता रहा। अपने आप को चारों ओर से घिरा जानकर भी उसने न तो अपने कदम पीछे खींचे और न ही आत्मसमर्पण किया। अपनी बहादुरी की दम पर उसने लगभग छह अंग्रेज पुलिस वालों को घायल कर दिया। वो लड़ता रहा आखिरी दम तक पर जब उसने देखा कि अब आखिरी गोली बची है और अंग्रेज अभी भी चारों ओर से गोलियाँ चला रहे हैं तो उस तरुण ने माँ भारती को नमन किया। अपने आप को भारत माँ के चरणों में कुर्बान करने की कसम तो वो पहले ही ले चुका था पर उसकी आँखों से बहते आंसू ये बयान कर रहे थे कि वह जो अपनी धरती माँ के लिए करना चाहता था, वह अधूरा रह गया। पर उसका संकल्प कि जीते जी कभी भी किसी अंग्रेज के हाथों नहीं आएगा, पूरा होने जा रहा था। उसने अपनी आखिरी गोली को चूमा, वहां की धरती का आलिंगन किया और उस गोली से अपने ही सर को निशाना बना कर रिवाल्वर चला दी। अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए और वहां मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब गोलियों की आवाज़ आनी बंद हुई तो लोगों ने देखा कि पुलिया के उत्तर भाग में एक 20-21 साल का लड़का लहूलुहान गिरा पड़ा है और अंग्रेज पुलिस उसे चारों ओर से घेरे हुए है। कोई कुछ समझ पता उससे पहले ही अंग्रेज उस नवयुवक की लाश को अपने कब्जे में लेकर चलते बने। आज़ादी का ये दीवाना कोई और नहीं, प्रफुल्ल चंद चाकी ही थे।

आज़ादी का ये वीर सपूत अपने बलिदान से मोकामा की धरती को भी अमर बना गया। अपने माता पिता की एकमात्र संतान होने के बावजूद चाकी ने देश की खातिर अपने को कुर्बान कर दिया। बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मौत के बाद पुलिस उपनिरीक्षक एनएन बनर्जी ने चाकी का सिर काट कर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश किया। यह अंग्रेज शासन की जघन्यतम घटनाओं में शामिल है। चाकी का बलिदान जाने कितने ही युवकों का प्रेरणा स्त्रोत बना और उसी राह पर चलकर अनगिनत युवाओं ने मातृभूमि की बलिवेदी पर खुद को होम कर दिया।

क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के सम्मान में आजाद भारत में एक स्मारक समिति भी बनी और उसकी ओर से दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में वर्ष 2006 में एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मोकामा के सांसद की मौजूदगी में चाकी की प्रतिमा के साथ ही उन पर डाक टिकट भी जारी करने की मांग की गई। लेकिन भारत माता के लाड़ले चाकी फिर भी विस्मृत और अबूझ ही बने रहे। उन पर 2010 में डाक टिकट जारी हुआ पर मोकामा में आज तक एक स्मारक भी नहीं बन सका है।

जिस स्थान पर चाकी शहीद हुए, वह जगह आज भी सरकार के कब्जे में है फिर भी वहां चाकी का स्मारक बनाने की अनुमति अब तक क्यों नहीं दी जा सकी है यह विचारणीय प्रश्न है। सत्यता तो यही है कि क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी को सरकारें भले ही भूल जाएं लेकिन आम जन मानस में जब भी क्रांतिकारियों की चर्चा होगी प्रफुल्ल चाकी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।आज उनके जन्मदिन पर पुनः नमन और यह विश्वास कि शायद अब उनकी स्मृतियों को संजोया जाएगा।

(कुमार कृष्णन-विनायक फीचर्स)

कौन हैं RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो शक्तिकांत दास की लेंगे जगह

परिवहन विशेष न्यूज

संजय मल्होत्रा के पास वित्त से जुड़े कामकाज को संभालने का लंबा तजुर्बा है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है। उनके काम करने के तरीके को पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी पसंद करते हैं। अपने तीन दशक के करियर में मल्होत्रा पावर फाइनेंस टैक्सेशन आईटी और माइंस जैसे विभागों में सेवाएं दे चुके हैं।

नई दिल्ली। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए गवर्नर होंगे। वह शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बजट 2024 को तैयार करने में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में गिने जाते हैं।

कौन है संजय मल्होत्रा

संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उन्हें अक्टूबर 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे। वह सरकारी कंपनी REC लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं।

मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। अपने तीन दशक के करियर में मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में सेवाएं दे चुके हैं।

सरकार की पसंद क्यों बने संजय मल्होत्रा?

मल्होत्रा के पास वित्त से जुड़े कामकाज को संभालने का लंबा तजुर्बा है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है। वह काफी समय से रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाल रहे हैं। उनके काम करने के तरीके को पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि मल्होत्रा अब आरबीआई गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं।

मल्होत्रा 11 दिसंबर (बुधवार) को आरबीआई गवर्नर का पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। वह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति काफी अहम है, क्योंकि भारत फिलहाल घटती जीडीपी ग्रोथ और बढ़ती महंगाई जैसे संकटों से जूझ रहा है।

अभी तक के 26 RBI गवर्नर में से 13 IAS

रिजर्व बैंक में अब तक कुल 26 गवर्नर हुए हैं। इनमें से 13 IAS अफसर हैं। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में काम करने से पहले वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला। मल्होत्रा के पास राज्य और केंद्र सरकार, दोनों स्तरों पर फाइनेंस और टैक्सेशन में विशेषज्ञता हासिल है।

संजय मल्होत्रा ऐसे समय में आरबीआई गवर्नर बनेंगे, जब केंद्रीय बैंक के सामने चुनौतियों की भरमार है। RBI पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव है, क्यों जीडीपी ग्रोथ सितंबर तिमाही में सात-तिमाही के निचले स्तर 5.4 फीसदी पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। खुदरा महंगाई ने भी नाक में दम कर रखा है।

गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, तो इन बातों का रखें ध्यान, बाद में नहीं होगी कोई परेशानी

कई बार हमें बच्चों की पढ़ाई शादी या घर बनवाने जैसे खर्चों के लिए गोल्ड लोन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन गोल्ड लोन लेने से पहले इसके नफा–नुकसान के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको अपने सोने की पूरी वैल्यू मिले। साथ ही आपको ब्याज या रीपेमेंट के समय किसी तरह का नुकसान ना हो। आइए गोल्ड लोन के बारे में सबकुछ जानते हैं

नई दिल्ली। गोल्ड ऐसी धातु है, जिसकी हमेशा दुनियाभर में अपनी एक अलग अहमियत रही है। इसके आभूषण पहनने का शौक आम महिलाओं से लेकर राजा महाराजों तक रहा। लेकिन, इसकी सबसे अहम भूमिका रही मौद्रिक प्रणाली में।

आज भी किसी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि उसके पास कितना गोल्ड भंडार है। कभी-कभी तो सरकारें सोना गिरवी रखकर कर्ज भी लेती हैं। आम लोग भी अक्सर गोल्ड लोन लेते हैं।

ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि गोल्ड लोन कैसे लिया जाता है, इसे कहां से लेना लिया जाता है और गोल्ड लोने लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

किन कामों के लिए लेना चाहिए लोन?

आप बच्चों की पढ़ाई, शादी या फिर इमरजेंसी में मेडिकल खर्च जैसे कामों के लिए गोल्ड ले सकते हैं। इसे दूसरे अन्य लोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन, गोल्ड लोन लेना तभी सही होता है, जब कुछ वक्त के लिए ही पैसों की दरकार हो। घर या जमीन खरीदने जैसे बड़े खर्च के लिए गोल्ड लोन का इस्तेमाल करने से जोखिमों पर पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए।

बैंक से लोन लें या NBFC से?

यह चीज आपकी सहूलियत पर निर्भर करती है। बैंक में कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन मिल जाता है। वहीं, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFC) ब्याज ज्यादा लेती हैं, लेकिन कर्ज की रकम भी ज्यादा देते हैं। NBFC का मुख्य धंधा ही सोने के बदले कर्ज देना होता है, इसलिए वहां गोल्ड लोन जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। हालांकि, आपके कर्ज लेने से अलग-अलग बैंकों और NBFC में ब्याज दर पता कर लेनी चाहिए। गोल्ड लोन की अच्छी बात है कि यह अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, कॉर्पोरेट लोन की तुलना में सस्ता पड़ता है।

एक्स्ट्रा चार्जेज पर भी गौर करें

गोल्ड लोन में भी दूसरे आम लोन की तरह प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो बैंकों और NBFC के हिसाब से अलग-अलग होती है। कुछ वित्तीय संस्थान इसमें रियायत भी देते हैं। प्रोसेसिंग फीस पर GST भी लगता है। कुछ बैंक वित्तीय संस्थान वैल्यूएशन फीस भी लेते हैं, जिसकी शुरुआत 250 रुपये से होती है। सर्विस चार्ज, SMS चार्ज और सिक्योर्ड कस्टडी फीस जैसे कुछ अन्य खर्चे भी होते हैं।

री-पेमेंट में कौन-सा ऑप्शन चुनें?

कर्ज देने वाले संस्थान आपको कर्ज की रकम और ब्याज का भुगतान (रीपेमेंट) करने के लिए ढेरों विकल्प देते हैं। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके पास हर महीने पैसे आते हैं, तो EMI में पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास एकमुश्त मूल भुगतान के साथ ब्याज भरने का विकल्प भी रहता है।

क्या है बीमा सखी योजना, कितने मिलेंगे पैसे? जानिए स्कीम से जुड़ने का पूरा प्रोसेस

परिवहन विशेष न्यूज

एलआईसी बीमा सखी योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को पहले तीन साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (11 दिसंबर) को हरियाणा से बीमा सखी योजना (Bima Sakhi Yojana) को लॉन्च किया। एलआईसी की बीमा सखी योजना (LIC Bima Sakhi Yojana) का मकसद आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना का हिस्सा बनने वाली महिलाओं को 'बीमा सखी' कहा जाएगा। उनका काम अपने इलाके की महिलाओं को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना और इस काम में उनकी मदद करना होगा।

बीमा सखी योजना क्या है?

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) की यह योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है, जो 10वीं पास हैं। उन्हें पहले तीन साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी वित्तीय समझ बढ़ाई जाएगी और उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा।

इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। वहीं, बीए पास बीमा सखियों को विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका भी मिल सकता है।

बीमा सखी बनने की योग्यता

बीमा सखी योजना के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।

उनके पास मैट्रिक/हाईस्कूल/10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए।

इस योजना के लिए 18 से 70 साल की महिलाएं ही अप्लाई कर सकेंगी।

तीन साल की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगी।

बीमा सखी बनने के फायदे

बीमा सखी योजना के तहत तीन साल की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं एलआईसी एजेंट के तौर पर नियुक्त हो सकेंगी। हालांकि, वे एलआईसी की रेगुलर कर्मचारी नहीं होंगी और न उन्हें नियमित कर्मचारियों वाला लाभ मिलेगा।

LIC की बीमा सखी (MCA योजना) के तहत चयनित महिलाओं को हर साल कुछ विशेष परफार्मेंस नॉर्म्स (Performance Norms) को पूरा करना होगा। इन्हें योजना योजना की सफलता और प्रतिभागियों की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

बीमा सखी को कितने पैसे मिलेंगे

बीमा सखी योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को तीन साल की ट्रेनिंग के दौरान कुल 2 लाख से अधिक रुपये मिलेंगे। इसमें पहले साल 7 हजार, दूसरे साल 6 हजार और तीसरे साल 5 हजार रुपये महीना मिलेंगे। इसमें बोनस कमीशन शामिल नहीं है। इसके लिए शर्त रहेगी कि महिलाएं जो भी पॉलिसी बेचेंगी, उनमें से 65 फीसदी अगले साल के आखिर तक सक्रिय (इन-फोर्स) रहनी चाहिए।

इसका मतलब है कि अगर किसी महिला ने पहले साल 100 पॉलिसी बेची है, तो इसमें से 65 पॉलिसी दूसरे साल के अंत तक प्रभावी रहनी चाहिए। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एजेंट न सिर्फ पॉलिसी बेचें, बल्कि उन्हें बनाए रखने की भी कोशिश करें।

बीमा सखी के लिए अप्लाई कैसे करें?

एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट https://licindia.in/test2 पर जाएं।

सबसे नीचे नजर आ रहे Click here for Bima Sakhi पर क्लिक करें।

यहां नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे डिटेल भरें।

अगर आप LIC इंडिया के किसी एजेंट/डेवलपमेंट ऑफिसर/कर्मचारी/मेडिकल एक्सामिनर से ताल्लुक रखते हैं, तो उसकी जानकारी दें।

सोना हुआ सस्ता, चांदी के बढ़े दाम; जानिए क्या है लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

आपको हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना चाहिए। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है- AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। सोमवार को सोने की कीमत में 190 रुपये की गिरावट आई।

नई दिल्ली। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार (9 दिसंबर) को सोने की कीमतों में गिरावट दिखी। हालांकि, चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ गए। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 190 रुपये गिरकर 78,960 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता यानी 24 कैरेट वाला गोल्ड 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

हालांकि, चांदी सोमवार को 350 रुपये बढ़कर 93,850 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह धातु 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। शुक्रवार को पीली धातु 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस बीच, एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 410 रुपये या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 77,029 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए।

सोने पर क्या है एक्सपर्ट की राय

MCX पर सोने की कीमतें बढ़ने के बारे में एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि इसकी वजह वैश्विक अस्थिरता है।

उन्होंने कहा, "भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ने से MCX पर सोने की कीमतें बढ़कर ₹77,200 पर पहुंच गईं। विद्रोही बलों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को हटा दिया, सीरियाई क्षेत्र में इजरायल की भागीदारी और तुर्की समर्थित विद्रोही गतिविधि की रिपोर्ट ने तनाव बढ़ा दिया।"

त्रिवेदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया के नेतृत्व संकट ने वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ा दिया। इसमें राष्ट्रपति यूं सुक येओल की आपराधिक जांच और महाभियोग से बचने की बात शामिल है। इन घटनाक्रमों ने सोने की रेंज को ₹76,500-₹78,000 तक बढ़ा दिया, जिससे निकट भविष्य में सुरक्षित निवेश की मांग में तेजी रहने की संभावना है।

हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें

आपको हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदना चाहिए। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है- AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है।

गोल्ड ETF में निवेश करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। बीते महीने यानी नवंबर में भारतीयों ने गोल्ड ETF में करीब 1,482 करोड़ रुपए निवेश किया। इसकी एक बड़ी वजह इक्विटी बाजार में भारी अस्थिरता रही। इससे पहले अक्टूबर में गोल्ड ETF में 1,961 करोड़ रुपये और सितंबर में 1,233 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

IRCTC की टिकट बुकिंग सर्विस बहाल, नए रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बदलने के लिए करना होगा इंतजार

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रेलवे की IRCTC साइट और ऐप फिलहाल काम नहीं कर रहा है। साइट पर जाने पर पॉप-अप आ रहा मेंटिनेंस एक्टिविटी के ई-टिकटिंग सेवा अगले एक घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। कृपया बाद में प्रयास करें। कैंसलेशन/टीडीआर फाइल करने के लिए कृपया ग्राहक सेवा नंबर 14646 0755-6610661 और 0755-4090600 पर कॉल करें या eticketsirctc.co.in पर मेल करें। आइए जानते हैं इसकी वजह।

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के वेबसाइट और ऐप पर ई-टिकटिंग सर्विस सोमवार को मेंटिनेंस एक्टिविटी के कारण एक घंटे के लिए ठप पड़ गई थी। इस दौरान साइट खोलने पर मैसेज आ रहा था, "मेंटिनेंस एक्टिविटी के ई-टिकटिंग सेवा अगले एक घंटे के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। कृपया बाद में प्रयास करें। कैंसलेशन/टीडीआर फाइल करने के लिए, कृपया ग्राहक सेवा नंबर 14646, 0755-6610661 और 0755-4090600 पर कॉल करें या etickets@irctc.co.in पर मेल करें।"

दोपहर बाद यह समस्या दूर हो गई और साइट खुलने लगी। हालांकि, यूजर्स अभी भी आज शाम 4 बजे से कल यानी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक नया रजिस्ट्रेशन, लॉग इन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे।

सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे थे यूजर

सोशल मीडिया यूजर IRCTC की साइट ठप (IRCTC Server Down) पड़ने की शिकायत कर रहे थे। IRCTC की वेबसाइट पर लॉगइन करने पर Downtime का मैसेज आ रहा था। इसमें लिखा है कि मेंटिनेंस वर्क की वजह से ई-टिकटिंग की सर्विस अगले 1 घंटे तक बंद रहेगी। टिकट कैंसल करने या TDR फाइल करने के लिए यात्रियों से कस्टमर केयर के नंबर पर फोन और ईमेल करने के लिए कहा जा रहा था।

आईआरसीटीसी के सर्वर का मेंटिनेंस अमूमन रात को होता है। लेकिन, इस बार सुबह 10 बजे जैसे ही तत्काल टिकट की बुकिंग का वक्त हुआ, सर्वर डाउन हो गया। इससे सोशल मीडिया पर यूजर्स की शिकायतों की बाढ़ आ गई है। इसमें खासतौर पर तत्काल टिकट की बुकिंग करने वाले लोग शामिल थे। यूजर्स IRCTC को टैग कर लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं।

क्या ये कोई साइबर अटैक है?

कई सोशल मीडिया पर अटकलें लगा रहे थे कि यह कोई साइबर अटैक है, क्योंकि IRCTC दिन के 10 बजे मेंटिनेंस नहीं करेगा, जो तत्काल बुकिंग का टाइम होता है। दरअसल, 10 बजे एसी कोच के लिए तत्काल के लिए टिकट बुक होता है। वहीं 11 बजे से नॉन-एसी यानी स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग होती है।

IRCTC फिलहाल सुपर ऐप पर काम रहा है। इसमें रेलवे से जुड़े सभी ऐप को मिलाकर एक ऐप बना जाएगा। इससे यात्रियों को ज्यादा सहूलियत होगी और वे टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन ट्रैक जैसे काम एक ही ऐप से कर सकेंगे। साइट डाउन होने को सुपर ऐप प्रोसेस से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

IRCTC की साइट पर 24 घंटे तक नहीं कर पाएंगे ये काम

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के मुताबिक, यूजर्स आज शाम 4 बजे से कल यानी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक नया रजिस्ट्रेशन, लॉग इन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह सर्वर मेंटिनेंस है। इससे पहले तकनीकी दिक्कतों के चलते सोमवार (9 दिसंबर) को सुबह करीब 10 बजे से वेबसाइट 12 बजे तक डाउन रही। इस दौरान वेबसाइट पर डाउनटाइम मैसेज दिखाई दे रहा था।

11 दिसंबर से खुलेगा मोबिक्विक का आईपीओ; जानिए प्राइस बैंड, जीएमपी समेत पूरी डिटेल

मोबिक्विक के आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल 95 रुपये का चल रहा है। इस हिसाब से मोबिक्विक के आईपीओ की लिस्टिंग 374 रुपये पर हो सकती है और निवेशकों को 34.05 फीसदी का शानदार लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मोबिक्विक आईपीओ से मिलने वाले 572 करोड़ रुपये को अलग-अलग काम में खर्च करेगी।

नई दिल्ली। फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (One Mobikwik Systems Limited) अपना आईपीओ ला रही है। यह देश की सबसे डिजिटल पेमेंट्स कंपनियों में शामिल है। मोबिक्विक आईपीओ से 572 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसका आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी धूम मचा रहा है। मोबिक्विक ने इससे पहले दो बार आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी मौके पर प्लान टाल दिया था।

Mobikwik IPO की पूरी डिटेल

मोबिक्विक ने आईपीओ के लिए 265 से 279 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है।

इसका लॉट साइज 53 शेयरों का है यानी आपको कम से कम 14,787 रुपये लगाने होंगे।

मोबिक्विक के आईपीओ को 11 से 13 दिसंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

शेयरों का अलॉटमेट 16 दिसंबर को होगा और रिफंड की प्रक्रिया 17 दिसंबर को शुरू होगी।

डीमैट में शेयर क्रेडिट 17 दिसंबर को होंगे, वहीं शेयर मार्केट में लिस्टिंग 18 दिसंबर को होगी।

Mobikwik IPO का GMP कितना है?

मोबिक्विक के आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल 95 रुपये का चल रहा है। इस हिसाब से मोबिक्विक के आईपीओ की लिस्टिंग 374 रुपये पर हो सकती है और निवेशकों को 34.05 फीसदी का शानदार लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ग्रे मार्केट एक अनधिकृत बाजार है, जहां आईपीओ की लिस्टिंग से पहले शेयरों का कारोबार होता है। हालांकि, यहां पर शेयरों का भाव काफी तेजी से ऊपर-नीचे होता रहता है।

Mobikwik IPO के पैसों का यूज कैसे करेगी

मोबिक्विक के आईपीओ में पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी जारी होगी। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले 572 करोड़ रुपये को अलग-अलग काम में खर्च करेगी। यह फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पेमेंट सर्विसेज के विस्तार में 135 करोड़ रुपये लगाएगी। वहीं, 107 करोड़ रुपये एआई, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी की रिसर्च एवं डेवलपमेंट में जाएंगे। पेमेंट डिवाइसेज पर पूंजीगत व्यय के लिए 70.2 करोड़ रुपये का खर्च होगा।

Mobikwik का बिजनेस और वित्तीय प्रदर्शन

मोबिक्विक मई 2024 तक भारत में सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट कंपनी थी। यह मोबाइल वॉलेट के अलावा भी कई तरह की वित्तीय सेवाएं देने लगी है। इसमें मोबिक्विक ZIP और ZIP EMI जैसे क्रेडिट प्रोडक्ट्स शामिल हैं। साथ ही, कंपनी अपने वॉलेट, UPI और Zaakpay के जरिए डिजिटल पेमेंट और मोबिक्विक एक्स्ट्रा के जरिए पीयर-टू-पीयर लेंडिंग देती है। Mobikwik का वित्त वर्ष 2024 के लिए रेवेन्यू 875 करोड़ रुपये का था। इसे 14.08 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट हुआ था।

नये आयामों को जाग्रत करेगा-'अंतरराष्ट्रीय विश्व ध्यान दिवस।'

भारत निरंतर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। योग हो या ध्यान, भारत ने युगों-युगों से विश्व को ऐसा कुछ दिया है, जो शायद ही विश्व के किसी अन्य देश ने संपूर्ण विश्व को दिया हो। शायद इसीलिए भारत को विश्व गुरू की संज्ञा दी जाती रही है। यह बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस' को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद अब 21 दिसंबर के दिन को विश्व 'विश्व ध्यान दिवस' के रूप में मनाने जा रहा है। सच तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद अब भारत ने विश्व को एक और भारतीय विधा-'ध्यान' से लैस किया है। उल्लेखनीय है कि ध्यान मनुष्य के विकारों का शमन करता है। वास्तव में, ध्यान का अर्थ है, अपने भीतर नए आयाम जागृत करना।जीवन का मूल उद्देश्य खिलने की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है, जहां तक पहुंचना संभव है। ध्यान खिलने के लिए खाद्य पदार्थ है। ध्यान से सकारात्मक स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है और आज के तनाव और अवसाद भरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नये जोश का सहज ही समावेश किया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि ध्यानस्थ रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का अभ्यास होता है और इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। आज के इस युग में स्वयं को ढूंढने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। ध्यान, मनुष्य को यंत्रवत होना छोड़ना सिखाता है और शान्ति, संयम(धैर्य) अहिंसा को जन्म देता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि ध्यान अनावश्यक विचारों को मन से निकालकर शुद्ध और आवश्यक विचारों को मस्तिष्क में जगह देता है। यह मनुष्य की आत्मिक शक्ति का विकास करता है और मनुष्य के तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक सम्बन्ध बनाता है और उसे बल प्रदान करता है। बहरहाल, पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र(यूएन) महासभा ने भारत द्वारा सह-प्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस (वर्ल्ड मेडिटेशन डे) घोषित किया है।भारत के साथ लिकटेंस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा उन देशों के मुख्य समूह के सदस्य थे, जिन्होंने 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'विश्व ध्यान दिवस' शीर्षक वाले प्रस्ताव को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित करने में अहम भूमिका निभाई। वास्तव में यह अत्यंत काबिले-तारीफ है कि भारत ने विश्व कल्याण की दिशा में यह एक बेहतरीन कदम उठाया है। युगों युगों से भारत का लक्ष्य समग्र मानवता का कल्याण रहा है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने सभ्यतागत सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' को लेकर चलता है और संपूर्ण विश्व को सदैव सकारात्मकता, शान्ति, संयम, आपसी सहयोग, मेलजोल, सौहार्द और सद्भावना का अनूठा संदेश देता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने सभ्यतागत सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम' को लेकर चलते हुए हाल ही में कोर समूह के अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 21 दिसंबर का दिन शीतकालीन अयनांत या संक्रांति का दिन होता है, जो भारतीय परंपरा के अनुसार 'उत्तरायण' की शुरुआत होता है, जो विशेष रूप से आंतरिक चिंतन और ध्यान के लिए वर्ष के एक शुभ समय की शुरुआत होती है। बहरहाल, विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति को विश्व स्तर पर एक और बड़ी कामयाबी है। हाल ही में शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को सभी देशों ने भारत के 'विश्व ध्यान दिवस' के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए एक तरफ से इसके पक्ष में वोटिंग की। बहरहाल, अंत में यही कहूंगा कि ध्यान मनुष्य मस्तिष्क और मनुष्य के समग्र कल्याण और विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि ध्यान अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। पाठकों को बताता चलूं कि असल में ध्यान का अर्थ है, अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं - आप एक ब्रह्मांड हैं। सच तो यह है कि ध्यान का अर्थ है-' पूरी तरह से बोध में स्थित होना।' वास्तव में पूरी तरह से मुक्त होने का यह(ध्यान) अकेला मार्ग है। कहना ग़लत नहीं होगा कि एक दशक में जिस तरह से 'योग दिवस' एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, जिसके कारण दुनिया भर में आम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, आने वाले समय में 'अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस' भी मानवता के समग्र कल्याण के संबंध में एक नायाब तोहफा व एक अनूठा आयाम बनकर उभरेगा।

(लेख मौलिक और अप्रकाशित है।)

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा

फर्जी निकला मरीज तो मेडिकल कॉलेज पर होगी कार्रवाई, NMC ने मान्यता के लिए रखी शर्त

सीट बढ़ाने की मंजूरी मांगने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नियम सख्त किए हैं। आयोग ने कहा है कि मंजूरी मिलने से पहले कॉलेज में फर्जी रोगियों की पहचान की जाएगी। अगर मरीज की स्थिति भर्ती लायक साबित नहीं मिली तो मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। कई कॉलेजों में ऐसे मामले सामने आने के बाद आयोग ने ये फैसला किया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नए संस्थान स्थापित करने या स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीट बढ़ाने की मंजूरी मांगने वाले मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फर्जी रोगियों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मरीज की स्थिति भर्ती लायक साबित नहीं मिली तो मेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने कहा कि इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। यह पहली बार है कि आयोग ने इस तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं। कुछ चिकित्सा संस्थानों द्वारा फर्जी मरीजों (ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है या जिन्हें भर्ती होने की जरूरत नहीं है) को भर्ती करने के मामले सामने आने के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

फर्जी मरीजों की पहचान के लिए मापदंड

दिशा-निर्देशों के अनुसार, निरीक्षण के दिन या उससे पहले के दिन बड़ी संख्या में मरीजों का भर्ती होना, एक ही परिवार के कई मरीजों का भर्ती होना या भर्ती हुए ऐसे मरीज जिनमें कोई समस्या नहीं है या मामूली समस्या है, जिनका उपचार ओपीडी में दवाएं देकर किया जा सकता है, 'फर्जी मरीजों' की पहचान करने का मापदंड हो सकता है।

आयोग ने कहा कि कुछ मेडिकल संस्थान काफी समय से मनमानी कर रहे हैं। काफी समय से यह देखा गया है कि कुछ चिकित्सा संस्थान/कॉलेज फर्जी मरीजों को भर्ती करते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) जांचकर्ताओं की टीम का चयन करेगा। एनएमसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांचकर्ता कॉलेज के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, संकाय, एईबीएएस डाटा, अन्य संकेतक और कॉलेज की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए मूल्यांकन करेंगे।

मुकेश 'कबीर' को मिला 'प्रेम सक्सेना स्मृति सम्मान'

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल। मध्यप्रदेश शीर्षक साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कीर्तिशेष साहित्यकार सम्मान के अंतर्गत इस वर्ष का गीतकार प्रेम सक्सेना स्मृति सम्मान देश के जाने माने गीतकार और लेखक डॉ.मुकेश ₹कबीर₹ को दिया गया।राजधानी भोपाल में तीन दिसंबर को आयोजित एक भव्य समारोह में कबीर को यह सम्मान केंद्रीय विश्व विद्यालय के कुलाधिपति श्री प्रकाश बरतूनिया ने प्रदान किया। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉ. नुसरत मेंहदी इस आयोजन की मुख्य अतिथि थीं और कार्यक्रम की अध्यक्षता निराला सृजन पीठ की निदेशक डॉ. साधना बलबटे ने की।मध्यप्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष डॉ राम बल्लभ आचार्य विशेष अतिथि थे।

गीतकार मुकेश ₹कबीर₹ को देश के विभिन्न मंचों पर गीतों की प्रस्तुति के लिए जाना जाता है साथ ही राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भारतीय संस्कृति,साहित्य और फिल्म से संबंधित लेखन के लिए भी मुकेश₹कबीर₹ विख्यात हैं। ₹हिंदुस्तान जिंदाबाद₹ इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है।(विभूति फीचर्स)

बीपीएससी परीक्षा विवाद: तेजस्वी यादव ने परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की, आयोग ने किया इनकार

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आगामी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है, जबकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित होगी।

तेजस्वी यादव की मांग

तेजस्वी यादव ने रविवार को लखीसराय में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ₹राज्य की एनडीए सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को लेकर चिंतित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में हो रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। छात्रों की मांगों के प्रति बीपीएससी के उदासीन रवैये के खिलाफ लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।₹

उन्होंने कहा कि आयोग को 13 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सर्वर में समस्याओं के कारण लाखों छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं।

आयोग का रुख

बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ₹इसे पहले ही 18 अक्टूबर से बढ़ाकर 4 नवंबर कर दिया गया था। परीक्षा के लिए 4.83 लाख से अधिक उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं। यह उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।"

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि तिथि को आगे बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल-मई 2025 से पहले आयोजित नहीं हो सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5-6 महीने की देरी होगी।

अभ्यर्थियों का विरोध

पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा के नियमों में कथित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा 'एक पाली, एक पेपर' के प्रारूप में आयोजित की जाए, न कि 'अंकों के सामान्यीकरण' प्रक्रिया का उपयोग करके, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई शिफ्ट में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समायोजित करती है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और नेताओं के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। आयोग ने परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है, जबकि विपक्षी दल और अभ्यर्थी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है और अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान कब होगा।

जान लेने की हद तक अंधा होता प्यार, गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कानपुर में फांसी पर झूला युवक

सुनील बाजपेई

कानपुर। प्रेम प्रसंग को लेकर अक्सर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं के संदर्भ में शायद यह भी कहा जा सकता है कि प्यार ऐसा वैसा नहीं बल्कि जान लेने की हद तक अंधा होता है। ...और जब प्रेमी या प्रेमिका को एक दूसरे से बिछड़ने का भय होता है अथवा ऐसा हो ही जाता है तो इंसान अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेने से भी नहीं चूकता।

कुछ ऐसा ही हुआ कमाई के मामले में लगभग 30 - 40 लाख सालाना टर्न ओवर वाले एक युवक के साथ जिसने प्रेमिका की कथित धोखेबाजी से दुखी होकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद उसके परिवार में कोहरा मचा हुआ है।

यह घटना नजीराबाद थाना क्षेत्र के कौशलपुरी की है जहां का रहने वाले युवक ने गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगा ली। वह मेट्रोमोनियल

वेबसाइट चलाता था,जिसका सालाना टर्न ओवर लगभग 30 40 लाख का था। उसकी लाश को पोस्टमॉर्टम हाउस भेजने के साथ ही नजीराबाद पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में गर्लफ्रेंड के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे।

घटना के बारे में प्राप्त विवरण के अनुसार कौशलपुरी नजीराबाद निवासी अर्पित सर्राफ (28) अपनी मां नीलम के साथ मिलकर मेट्रोमोनियल वेबसाइट सदगुरू के नाम से चलाते थे। वेबसाइट के जरिए अच्छा कारोबार मिल रहा था। इनके व्यापार का 25-30 लाख रुपए का टर्नओवर है। मौके पर पहुंची पुलिस को अर्पित के ममेरे भाई अभिनव ने बताया- अर्पित किसी गर्लफ्रेंड से बात करता था। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों घूमने-फिरने भी जाते थे।

ममेरे भाई अभिनव ने पुलिस को यह भी बताया कि बताया कि अर्पित की गर्लफ्रेंड के जीवन में कोई और आ गया था। इसके बाद वो अर्पित से दूर रहने लगी थी। उससे बातचीत कम कर दी थी और ब्रेकअप की बात करती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात चल रही थी।

अभिनव के अनुसार अर्पित उसे मनाने का प्रयास कर रहा था मगर वो मान नहीं रही थी। इसी नोकझोंक में अर्पित ने वीडियो कॉल के दौरान ही मां की चुनरी से फांसी का फंदा बनाकर उससे लटक कर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस चर्चा का विषय बनी इस घटना की छानबीन कर रही है।

डाकघर की विशेष स्कीम: 10 लाख का निवेश, 30 लाख का फंड – जानें कैसे!

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

अगर आप निवेश के जरिए बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की एक विशेष योजना आपके लिए है। इसमें निवेश पर आपको लाखों का फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं इस स्कीम की पूरी जानकारी।

पोस्ट ऑफिस की इस खास स्कीम में, अगर आप 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको पूरे 30 लाख रुपये मिल सकते हैं। ये योजना न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसे सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है।

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए निवेशकों को एक निश्चित अवधि तक पैसे निवेश करने होंगे। ब्याज दर और निवेश अवधि के अनुसार, रिटर्न की गणना की जाती है।

यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक है जो रिस्क फ्री और सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। यह खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है जो अपने रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की योजना बना रहे हैं।

अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि आप पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें।

तो इंतजार मत कीजिए! पोस्ट ऑफिस की इस शानदार योजना का लाभ उठाइए और अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाइए।

गलत रास्ता गूगल मैप्स; रायपुर होते हुए कंधमाल पहुंचे

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर: गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता एक बड़े हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर। गूगल मैप में गलत रूट दिखाने के कारण चावल लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहा ट्रक तीन दिनों से कंधमाल जिले के गजलबाड़ी घाट पर फंसा हुआ है।चावल से भरा एक ट्रक विशाखापत्तन से निकलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहा था।ट्रक ड्राइवर ने गूगल मैप देखा और शॉर्टकट लेने की कोशिश की। लेकिन गूगल मैप्स ने गलत रास्ता दिखाया। ट्रक रायपुर की ओर जा रहा था जब वह कंधमाल-गंजाम सीमा पर गजलबाड़ी घाट पर नान ओसरिया पहुंचा। ट्रक चालक और खलासी बड़े हादसे से बाल-बाल बच गये। तीन दिन से ट्रक उस बेकार सड़क पर फंसा हुआ है, जिससे अन्य लेन का उस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। उधर, चालक का कहना था कि लेन खराब हो गयी है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।

इस्लामिक देश सीरिया में खून खराबे का दौर

(मनोज कुमार अग्रवाल -विभूति फीचर्स)

इस्लामिक देश सीरिया में तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों बशर अल-असद देश छोड़ने को मजबूर हुए,ये सब जानना दुनिया भर के लिए आज जरूरी है।दरअसल, 2011 में भी सीरियाई नागरिकों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे। लेकिन तब असद ने इसका जवाब क्रूरता से दिया था। जिससे एक गृहयुद्ध शुरू हुआ, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। 13 साल बाद 8 दिसंबर को असद देश छोड़कर भाग गए और विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। असलियत यह है कि कब्जे के बाद भी विद्रोहियों के लिए देश चलाना मुश्किल हो रहा है।

करीब आठ साल तक सीरिया के गृहयुद्ध में मोर्चे स्थिर रहे, जहां असद की सरकार रूस और ईरान के समर्थन से देश के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रही थी, जबकि विभिन्न विपक्षी समूह उत्तर और पश्चिम में क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए हुए थे लेकिन 27 नवंबर को कहानी बदल गई जब हयात तहरीर अल-शाम नामक इस्लामिक समूह, जो पिछले पांच सालों से इडलीब प्रांत पर शासन कर रहा था उसने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया।कुछ ही दिनों में, उन्होंने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो, हमा, होम्स पर कब्जा किया और आखिरकार राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा जमा लिया।

सीरिया के उत्तर-पश्चिम में इस्लामी आतंकवादियों ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेना के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला किया और नाटकीय रूप से क्षेत्रीय लाभ हासिल किया।सीरियाई गृह युद्ध, जो 2011 में अरब स्प्रिंग से प्रेरित सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच शुरू हुआ था, 2016 के अंत में एक स्थिर चरण में प्रवेश कर गया था, जब सरकार ने अपने अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया था।

2015 में, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा सीरिया में सेना भेजने का फैसला करने से पहले, असद शासन पतन के कगार पर था। दमिश्क और अलावी-प्रभुत्व वाले तटीय शहरों को छोड़कर, उसने अधिकांश आबादी वाले शहरों को खो दिया था।फ्री सीरियन आर्मी, जबात अल-नुसरा (अल- कायदा की सीरिया शाखा) और इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) के रूप में कई विद्रोही और जिहादी गुट थे।

रूसी हस्तक्षेप ने गृह युद्ध को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जबकि अमरीका द्वारा समर्थित कुर्द मिलिशिया ने पूर्व में और कुर्द सीमावर्ती शहरों में आई.एस. से लड़ाई लड़ी, वहीं डुओसिया, ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा समर्थित सीरियाई सेना ने अन्य देशों से लड़ाई लड़ी।

आज सीरिया में तीन मुख्य 'खिलाड़ी' हैं। सबसे महत्वपूर्ण असद सरकार है, जिसे ईरान, ईराक और रूस के शिया मिलिशिया का समर्थन प्राप्त है। दूसरा 'खिलाड़ी' सीरियन डैमोक्रेटिक फोर्सेस (एस.डी.एफ.) है, जो मूल रूप से पीपुल्स प्रोटैक्शन फोर्सेस (वाई.पी.जी.) से जुड़ा एक प्रमुख मिलिशिया समूह है, जो सीरियाई कुर्दिस्तान (रोजावा) को नियंत्रित करने वाला मुख्य सीरियाई कुर्द मिलिशिया है। तीसरा 'खिलाड़ी' हयात तहरीर अल-शाम (एच.टी.एस.) है, जो मुख्य सरकार विरोधी बल है जो इदलिब पर नियंत्रण रखता है। आज इसे सीरियन नैशनल आर्मी (एस.एन.ए.) कहा जाता है।एच.टी.एस. का नेतृत्व 42 वर्षीय

सीरियाई आतंकवादी अबू मोहम्मद अल-जौलानी कर रहा है।

जौलानी 20 साल की उम्र में वर्ष 2003 में अमरीकी कब्जे से लड़ने के लिए ईराक चला गया था और अल-कायदा में शामिल हो गया था। जब ईराक में अल-कायदा की कमान अबू बकर अल बगदादी के हाथों में थी, तो जौलानी उसके करीबी लैफ्टिनैंटों में से एक के रूप में उभरा।

जब दुनिया का ध्यान सीरिया की ओर गया, तो जौलानी ने इदलिब में अपना साम्राज्य धीरे-धीरे बढ़ाया। इस्लामिक स्टेट हार गया और बगदादी मारा गया। जौलानी ने सबसे पहले अल-नुसरा फ्रंट का नाम बदलकर जबात फतेह अल-शाम कर दिया। बाद में, नाम बदलकर फिर से हयात तहरीर

अल-शाम कर दिया। जौलानी एक यू.एस. द्वारा नामित आतंकवादी है।

जौलानी हमेशा कहा करता था कि असद शासन को गिराना उसके उद्देश्यों में से एक था। रूस ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन से युद्ध शुरू किया। मॉस्को इस युद्ध में व्यस्त है, और उसने सीरिया से हजारों सैनिकों को वापस भी बुला लिया है।

पिछले एक साल में, सीरिया में इसराईली हवाई हमलों में कई वरिष्ठ ईरानी जनरल मारे गए। पिछले कई वर्षों में सीरिया में इसराईल के बार-बार हवाई हमलों ने ईरानी सेना को काफी हद तक कमजोर कर दिया है।

ईरान, हिजबुल्लाह और रूस के प्रत्यक्ष समर्थन के बिना, सीरिया के सैनिक असुरक्षित थे। 2016 में अलेप्पो पर फिर से कब्जा करने में असद को चार साल लग गए परन्तु एच.टी.एस. के हाथों उसे खोने में उसे सिर्फ चार दिन लगे।

देश के अन्य हिस्सों में विद्रोही समूहों ने सरकारी ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया, खासकर दक्षिण में। दमिश्क में हिंसा के बीच चौक चौराहों पर आजादी के नारे लग रहे हैं। विद्रोहियों ने कहा है कि₹ यह 50 वर्षों के उत्पीड़न और 13 साल के अपराध, अत्याचार और विस्थापन का अंत है₹। असद देश छोड़ कर भाग चुके हैं लेकिन असद को खारिज करना जल्दबाजी होगी, जो पहले भी एक बार वर्षों तक चले गृह युद्ध से बच गए थे। ऐसा लगता है कि सीरिया रक्तपात के एक और लंबे दौर में फंसता चला जा रहा है।भविष्य में भी स्थिरता और शांति स्थापना की कोई गारंटी नहीं है यह विश्व भर के ज्यादातर इस्लामिक देशों की समस्या है कि वहां लगातार खून खराबा और आतंक की अवधारणा पोषित की जाती रही है ऐसा भविष्य में भी बने रहने की पूरी गुंजाइश है।

प्यार है पहला-पहला!

न जाने कितनी बार पढ़ा है
मैंने तुम्हारा ये चेहरा।
खामोश-सी तुम्हारी आँखें,
कोई राज है इनमें गहरा।
ये कितनी अच्छी बात है,
नहीं है जमाने का पहरा।
ऐ यारा तू इतनी जल्दी,
अपनी ज़ुल्फ़े यूँ ना लहरा।
जी भर के देख लेने दे,
खिड़की में बैठकर चेहरा।
हुस्न की क्या बात करूं,
चाँद-सा मुखड़ा रूपहला।
माना खूबसूरत हो तुम,
तुम्हारा रूप भी है सुनहरा।
दे भी दो मुझे तवज्जो,
यह मेरा प्यार है पहला-पहला।

संजय एम. तराणेकर

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023